▶▶ कृषि ▶▶ विश्लेषण ▶▶ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

चैत्र–वैशाख 2080, अप्रैल 2023

डालर की सत्ता से मुक्ति का मार्ग

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र झलक

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–31, अंक–4
चैत्र–वैशाख 2080 अप्रैल 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – 6
डालर की सत्ता से मुक्ति का मार्ग
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा
भारतीय रुपए में वैश्विक व्यापार निपटान की राह आसान ..... अनिल तिवारी

10 स्वावलंबी
उद्यमिता, स्वरोजगार व स्वावलम्बन ..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

12 विश्लेषण
मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) कितना उपयोगी? ..... केके श्रीवास्तव

14 आर्थिकी
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ मंगल संकेत ..... विक्रम उपाध्याय

16 शिक्षा
उच्च शिक्षा के के मोर्चे पर बेहद सावधानी की जरूरत ..... डॉ. जया कक्कड़

18 मुद्दा
अदानी प्रकरणः इतना हंगामा है क्यों बरपा? ..... अनिल जावलेकर

20 ई–कॉमर्स
ई–कॉमर्स में गेम चेंजर हो सकता है 'ओएनडीसी' ..... स्वदेशी संवाद

22 कृषि
विकसित राष्ट्र की आधारशिला रखने वाला बजट ..... देविन्दर शर्मा

24 कृषि
बढ़ते ही जा रहे है खेती पर खतरे ..... शिवनंदन लाल

26 स्वदेशी
राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी जी का 'स्वदेशी चिंतन' ..... डॉ. युवराज सिंह

28 भाषा
मातृभाषाः सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला ..... डॉ. जया शर्मा

30 जल प्रबंधन
कहां गुम हो रही छोटी नदियां ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

33 विचार
मंदी के माहौल में विकसित देशों की मदद करता भारत ..... प्रहलाद सबनानी

पाठकनामा

इंसाफ के इंतजार में यौन उत्पीड़ित बच्चे

बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित खबरें यूं तो हर दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, लेकिन इन दिनों दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा खुद के पिता पर यौन–शोषण के आरोप लगाने के बाद इस तरह के मामलों की चर्चा देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंची है। सरकार ने संसद में बताया है कि रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर सारे कदम कागजी ही साबित हो रहे हैं। हमारे देश में बच्चों के बहुस्तरीय उत्पीड़न और उनके यौन शोषण जैसे अपराधों की रोकथाम में जब पहले के कानूनी प्रावधान नाकाफी साबित हुए, तब पार्क–सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जैसी विशेष व्यवस्था की गई। मगर आज भी हालत यह है कि इस कानून के तहत परिभाषित अपराधों के शिकार बहुत सारे बच्चे और उनके परिजन इंसाफ की आस में बैठे हैं। सवाल है कि बच्चों को जघन्य अपराधों से बचाने और न्याय दिलाने के लिए विशेष तंत्र गठित किए जाने के बावजूद ऐसे मामलों की सुनवाई या इस पर फैसला आने की रफ्तार इस कदर धीमी क्यों है?

हाल ही में संसद में सरकार ने जानकारी दी कि देश भर में बच्चों के खिलाफ अपराध की धाराओं के तहत दर्ज 50,000 से ज्यादा मामलों में बच्चों को न्याय का इंतजार है, ये वे मामले हैं जो एक साल के भीतर दर्ज किए गए हैं। जहां कम से कम दर्ज मामलों को ही निर्धारित या फिर जल्दी निपटाने और न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वही अब केंद्र सरकार इससे संबंधित मुकदमों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समय को 3 वर्ष और बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि यौन शोषण और इस प्रकृति के अन्य उत्पीड़न के लिहाज से बच्चे हर जगह और हर वक्त किस स्तर के जोखिम से गुजरते हैं। घर के बाहर से लेकर दहलीज के भीतर तक उन्हें शोषण को झेलना पड़ता है। स्वाति मालीवाल का मामला अकेला नहीं है सामाजिक दायरा और सोचने समझने के सलीके इस कदर तंग नजरी के शिकार हैं कि कई बार आरोपी व्यक्ति अपने परिवार या पड़ोसी की होने की वजह से मामले को दबा दिया जाता है।कहा जा सकता है कि एक ओर समाज में परंपरागत मानस और रूढ़ धारणाओं की वजह से तो दूसरी ओर सरकारी और न्यायिक तंत्र की जटिल व्यवस्था के चलते बच्चों को अपने खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से उपजी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शोषण के चक्कर में पिसते और इंसाफ से वंचित बच्चों से जैसी पीढ़ी तैयार होगी वह किसी भी समाज और देश के हित में नहीं होगी।

जयेंद्र नाथ मिश्र, लक्ष्मीपुर, बलिया (उत्तर प्रदेश)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और "महिला सम्मान बचत पत्र" इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब 'विदेशी प्रभाव' को बर्दाश्त नहीं करेगा।

किरण रिजिजू, कानून मंत्री, भारत

एसवीबी के पतन के बाद, सरकार भारतीय स्टार्टअप्स को संभालने के लिए कार्रवाई में जुट गई, जिनके पास बैंक में धन या जमा राशि थी। हमने यह सुनिश्चित किया कि जो भी जमा राशि वे भारतीय बैंकों में स्थानांतरित करना चाहते थे, पूरी प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण रूप से निष्पादित किया गया था।

अश्विनी वैष्णव, आईटी व संचार मंत्री, भारत

अमेरिकी डॉलर को विदेशी मुद्रा भंडार और अंतरराष्ट्रीय भुगतान के रूप में पसंद किया जाता है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत अब रुपये में अंतरराष्ट्रीय भुगतान कर रहा है। इसका असर भी कुछ समय बाद दिखने लगेगा। कई देश रुपया स्वीकार कर रहे हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

एक और भ्रामक रिपोर्ट

मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में 'सस्टेंनेबल डेवलपमेंट सोल्युशन नेटवर्क' द्वारा 'विश्व खुशी रिपोर्ट', 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भी भारत को विश्व खुशी सूचकांक में 126वें स्थान पर दिखाया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में भारत को पिछले वर्ष 136वें पायदान से बेहतर 126वें पायदान पर रखा गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे कई मुल्क जो विभिन्न परिस्थितियों के चलते किसी भी हाल में खुशी के मामले में भारत से बेहतर हो ही नहीं सकते, उन्हें भी भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए साऊदी अरब जिसमें तानाशाही व्यवस्था है उसे 30वें स्थान पर, यूक्रेन जो युद्ध में बर्बाद हो चुका है उसे 92वें स्थान पर, तुर्की जो महंगाई के कारण टूट चुका है उसे 106वें स्थान पर, दुनिया के सामने भीख का कटोरा लिए खड़े पाकिस्तान 108वें स्थान पर दिखाया गया है और पूरी तरह से दिवालिया हो चुका श्री लंका 112वें स्थान पर है और भारत जो खाद्य पदार्थों की .ष्टि से ही नहीं बल्कि विभिन्न अन्य मामलों में दुनिया के उन तमाम मुल्कों से कहीं बेहतर है जो इस रिपोर्ट में भारत से बेहतर स्थिति में दिखाए गए हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं।

यह पहली बार नहीं कि इस प्रकार की भ्रामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। हाल ही में 'वेल्ट हंगर हिल्फे' नाम के एक जर्मन एजेंसी द्वारा भी भारत को भूखमरी सूचकांक में 121 देशों की तालिका में 107वें स्थान पर रखा था। उसमें दिलचस्प बात यह थी कि उस सूची में यूक्रेन ही नहीं बल्कि ईराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बंगलादेश, और जोर्डन आदि देशों को भी भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया है। यह उस रेटिंग एजेंसी पर एक सवालिया निशान लगाता है। समझना होगा कि 'वेल्ट हंगर हिल्फे' का भुखमरी सूचकांक कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। भारत द्वारा पिछले कुछ दशकों में जो उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे लोगों का जीवन स्तर पहले से कहीं बेहतर हुआ है और भारत पिछले कुछ सालों में विश्व की दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ता हुआ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, दुनिया की कई शक्तियों को भारत की यह प्रगति हजम नहीं हो रही। ऐसे में वे विभिन्न हथकंडे अपनाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर छोड़ते नहीं हैं।

विश्व खुशी रिपोर्ट की शुरूआत वर्ष 2012 में हुई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल 'सस्टेंनेबल डेवलपमेंट सोल्युशन नेटवर्क' द्वारा प्रकाशित की जाती है। कहा जाता है कि यह रिपोर्ट दुनिया भर से एक औचक यानि झटपट सर्वेक्षण के आधार पर बनाई जाती है। लेकिन देखा जाये तो इस प्रकार की अवधारणा की शुरुआत वास्तव में 1974 में भूटान के तत्कालीन नरेश जिगमे सिंगे वांचुक द्वारा 'राष्ट्रीय खुशी सूचकांक' के नाम से की गई। उनका मानना था कि उत्पादन में वृध्दि मात्र खुशी का सबब नहीं बन सकती। इसलिए विकास के मापन में खुशी एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए। उसके उपरांत भूटान देश ने अपने लोगों की खुशी के उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी प्रारंभ की। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर के देशों को वहां के लोगों की खुशी के आधार पर सूचीबध्द करने का काम शुरु हुआ। 2009 में प्रकाशित 'हैप्पी प्लैनेट सूचकांक' के नाम की सूची को देखने से पता चलता है कि अमरीका जो दुनिया का अत्यंत विकसित राष्ट्र है, 'हैप्पी प्लैनेट सूचकांक' के आधार पर 143 देशों की सूची में 114वें स्थान पर था। सिंगापुर 49वें, फ्रांस 71वें, कनाडा 89वें, इंगलैंड 74वें, जर्मनी 51वें और भारत 35वें पायदान पर था। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के वर्तमान सूचकों के आधार पर मानव विकास सूचकांक की सूची में 131वें स्थान पर खड़ा भूटान आश्चर्यजनक रूप से खुशी सूचकांक के आधार पर 17वें स्थान पर खड़ा था। वास्तव में प्रथम 20 स्थानों में जगह बनाने वाले राष्ट्रों में भूटान एक मात्र विकासशील देश था। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान में विश्व खुशी सूचकांक के हिसाब से फ़िनलैंड जो पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट में 59वें स्थान पर था। जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया 'खुशीः विकास के एक समग्र परिभाषा की ओर'। अप्रैल 2012 में पहली विश्व खुशी रिपोर्ट प्रकाशित की गई और उसके उपरांत हर वर्ष 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की जाती है। इस संदर्भ में विभिन्न देशों की खुशी के पैमाने पर रैंकिंग 'कैन्ट्रिल लेडर सर्वे' यानि कैन्ट्रिल सीढ़ी सर्वेक्षण के पैमाने पर की जाती है। विचारणीय बात यह है कि भूटान की तर्ज़ पर विश्व में जो खुशी सूचकांक सबसे पहले प्रकाशित हुआ था उसमें अमरीका और यूरोप के देश खुशी सूचकांक में बहुत पीछे थे। लेकिन जब से यह काम पश्चिमी देशों के हाथ में आया, तब से एशियाई देश पीछे खिसक गए और यूरोपीय देश पहली पंक्ति में आ गये। यानि कहा जा सकता है कि भौतिक संपत्ति और आमदनी फिर से खुशी का पैमाना घोषित हो गयी है और कम आय वाले देशों को अपनी मन मर्ज़ी से ऊपर–नीचे करने का काम हो रहा है।

भारत जिसे 126वें स्थान पर बताया गया है, आज खाद्य पदार्थों के संदर्भ में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया भर को अन्न उपलब्ध करा रहा है, जहां पिछले कुछ सालों में घरविहीन और कच्चे घर वाले 3 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसने कोविड की त्रास्दी का दुनिया भर में सबसे बेहतर तरीके से सामना किया है, जहां लगभग सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है, जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे और उसके लिए 80 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा मुत राशन दिया जा रहा है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, स्वच्छता आदि में अभूतपूर्व विकास हो रहा है, उसे पाकिस्तान, बंगलादेश और म्यांमार से पीछे दिखाए जाने से भारत की साख तो कम नहीं होती है लेकिन उस संस्था की साख पर बट्टा जरूर लगता है जो ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

डालर की सत्ता से मुक्ति का मार्ग

पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक हमने डॉलर की मजबूती देखी है। पहले विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों ने संयुक्त राज्य अमरीका को आपूर्ति के बदले सोना देना शुरू किया, जिसके बलबूते अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद विभिन्न देशों ने अपनी करेंसियों को डॉलर के साथ जोड़ दिया और इसके साथ ही दुनिया में 'गोल्ड स्टैण्डर्ड' का अंत हो गया और साथ ही साथ डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा करेंसी बन गई। सभी मुल्क अपने विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा से ज्यादा डॉलर के रूप में रखने लगे। 1999 तक दुनिया के मुल्कों के कुल विदेशी मुद्रा भंडार 70 प्रतिशत तक डॉलर में रखे जाने लगे।

1999 में यूरोपीय साझा करेंसी यूरो का उदय हुआ और कुछ यूरोपीय देशों को छोड़कर शेष सभी ने देर–सबेर अपनी करेंसी के बदले यूरो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका असर डॉलर पर भी पड़ा और कुछ यूरोपीय करेंसियों और डॉलर के बदले अब यूरो विदेशी मुद्रा भंडारों के लिए पसंद किया जाने लगा और विदेशी मुद्रा भंडारों में वर्ष 2021 के प्रारंभ तक आते–आते डॉलर का हिस्सा मात्र 59 प्रतिशत ही रह गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से यह हिस्सा और कम होकर वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही तक मात्र 55 प्रतिशत ही रह गया दुनिया भर में अब डॉलर के प्रति आसक्ति कम होती दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि डॉलर अभी भी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि कुछ करेंसियों को छोड़कर दुनिया की लगभग समस्त करेंसियों की तुलना में डॉलर साल दर साल मजबूत और अधिक मजबूत होता रहा है। इंग्लैंड के पाउंड की तुलना में देखें तो जहां आज एक अमरीकी डॉलर 0.81 ब्रिटिश पाउंड के बराबर है, वही वर्ष 2014 में यह औसतन 0. 59 ब्रिटिश पाउंड के बराबर था। दूसरी करेंसियों की हालत भी लगभग इसी प्रकार रही। एक अमरीकी डॉलर जो वर्ष 2014 में 0.75 यूरो के बराबर था, आज वह 0.93 यूरो के बराबर पहुंच चुका है। आज एक अमरीकी डॉलर 131.51 जापानी येन के बराबर है, यही 2014 में औसतन 121 जापानी येन के बराबर था।

धीरे–धीरे डॉलर से मुक्ति प्राप्त करती दुनिया की आर्थिक तस्वीर कैसी होगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह तस्वीर तमाम उन देशों के लिए अवश्य मंगलकारी होगी जो लगातार डॉलर की तुलना में अपनी करेंसियों के अवमूल्यन की त्रास्दी से गुजर रहे हैं।

– डॉ. अश्वनी महाजन

इतिहास में डॉलर के प्रति दुनियाभर के मुल्कों की आसक्ति के कारण डॉलर दुनिया की अन्य करेंसियों, खासतौर पर विकासशील देशों की करेंसियों की तुलना में लगातार मजबूत होता गया। जहां 1980 में एक डॉलर मात्र 7.86 भारतीय रूपए के बराबर था और आज यह 82.20 रूपए तक पहुंच चुका है। कई अन्य मुल्कों की करेंसियों के मुकाबले तो यह और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। शायद इसीलिए दुनिया के तमाम मुल्क डॉलर को ही रिजर्व करेंसी रखने और अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डॉलरों में ही करने में रूचि रखते रहे हैं। डालर की इसी बढ़ती मांग के चलते डॉलर और अधिक मजबूत होता गया।

लेकिन पिछले कुछ समय से रिजर्व कैरेंसी के नाते डॉलर की मांग कम होती जा रही है। जानकार लोग इस प्रवृत्ति को डी–डॉलरीकरण का नाम दे रहे हैं। जैसे पूर्व में पूरी दुनिया का डॉलरीकरण हुआ, लेकिन अब दुनिया में डी–डॉलरीकरण हो रहा है। समझने की आवश्यकता है कि जहां अमरीकी डॉलर इतिहास में सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है, तो भी दुनिया में रिजर्व करेंसी के नाते डॉलर के प्रति आसक्ति क्यों कम हो रही है। यदि विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण फरवरी

2022 से चल रहा रूस–यूक्रेन युद्ध है। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों का कहना है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया है, इसलिए दुनिया के सभी देशों को रूस से सम्बंध विच्छेद कर लेने चाहिए। अमरीका ने न केवल रूस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि वैश्विक भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से उसके बेदखल कर दिया है। माना जा रहा है कि भुगतान प्रणाली पर अमरीका और यूरोपीय देशों के दबदबे के चलते रूस के डॉलरों में विदेशी मुद्रा भंडारों की निकासी नहीं हो सकती। यानि रूस को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने के लिए अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा भुगतान प्रणाली को युद्ध के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में स्वभाविकतौर पर रूस और उसके मित्र देश अब किसी भी हालत में अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को डॉलरों में रखने के लिए तैयार नहीं।

अमरीका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के चलते दुनिया के मुल्कों पर यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि वे रूस से कच्चा तेल न खरीदें। रूस अपने ऊपर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते सस्ते दामों पर कच्चा तेल बचने को तैयार है। ऐसे में भारत ने तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को धत्ता दिखाते हुए रूस से ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। जहां रूसी तेल का हिस्सा भारत के तेल आयात में मात्र 1 प्रतिशत ही था, वह बढ़कर अब 35 प्रतिशत पहुंच चुका है। रूस ने तो यहां तक कहा है कि वो भारत से रूपयों में भी व्यापार करने के लिए तैयार है।

यही नहीं रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण अब अन्य देश अमरीका और यूरोपीय देशों के जहाजों और बीमा कंपनियों की सेवा भी नहीं ले सकते हैं। ऐसे में भारत और कई अन्य देश अब रूसी और अन्य गैर अमरीकी और

गैर–यूरोपीय जहाजों और बीमा कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। यानि अमरीका और यूरोप के रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के चलते अब पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंधों की अपनी दादागिरी के कारण स्वयं ही भारी नुकसान उठा रहे हैं। भारतीय बैंकों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में बढ़ती जा रही है।

19 देशों के साथ रूपयों में होंगे भुगतान

एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के इस्तेमाल में कमी आती जा रही है, भारत ने भी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कवायद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा भुगतान प्रणाली को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद भारत ने रूस से तेल आयात के बदले रूपयों में भुगतान करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। पिछले साल जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पत्रक के माध्यम से आयात और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान निपटारों को रूपयों में करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है। यह भारतीय रूपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की तरफ पहला कदम माना जा रहा है, उसके बाद दिसंबर में पहली बार रूस के साथ भुगतान निपटारे की शुरूआत हो चुकी है। भारत सरकार के प्रयासों से अभी तक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रूस और युनाईटेड अरब अमीरात समेत 19 देशों के बैंकों को 'स्पेशल वोस्त्रो रूपी एकाउंट' खोलकर रूपयों में भुगतान निपटारे करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। गौरतलब है कि 19 देशों की इस सूची में कई देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का विदेशी व्यापार काफी बड़ी मात्रा में होता है। यदि इन देशों के साथ भुगतान निपटारे अब रूपयों में होने लगेंगे तो देश में डॉलरों की मांग निश्चित रूप में कम होगी। दुनिया में डी–डॉलरीकरण के तरफ भारत का यह प्रयास चाहे छोटा ही सही, लेकिन भारत के लिए तो निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा।

विश्व को डालरों की सत्ता से मुक्ति के बाद दुनिया में डॉलर की कीमत पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब डॉलर की मजबूती की प्रवृत्ति पर भी कहीं न कहीं लगाम लगेगी। उसका फायदा दुनिया के तमाम मुल्कों को हो सकता है, जिनकी कैरेंसियां डॉलर के मुकाबले अब बेहतर हो सकेंगी। धीरे–धीरे डॉलर से मुक्ति प्राप्त करती दुनिया की आर्थिक तस्वीर कैसी होगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह तस्वीर तमाम उन देशों के लिए अवश्य मंगलकारी होगी जो लगातार डॉलर की तुलना में अपनी करेंसियों के अवमूल्यन की त्रासदी से गुजर रहे हैं। ❑❑

भारतीय रुपए में वैश्विक व्यापार निपटान की राह आसान

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारतीय रुपए में भी होगा। निर्णय के अनुसार भारतीय निर्यातकों और आयातकों को व्यापार के लिए डालर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। दुनिया का कोई भी देश भारत से सीधे बिना अमेरिकी डालर के व्यापार कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस कदम से भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक करेंसी के लिए स्वीकार करवाने की दिशा में मदद मिलेगी। इससे भारत के वैश्विक उद्देश्यों को साधने के साथ–साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। इस तंत्र को लागू करने से पहले बैंकों को आरबीआई के विदेशी मुद्रा विभाग से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता भी होगी। ऐसे में इसके तात्कालिक प्रभाव का भी आकलन करना आवश्यक होगा।

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे पहले बढ़े हुए व्यापार और एफडीआई प्रवाह के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी एकीकरण को बढ़ाएगा। भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी। वर्ष 2021–22 में दुनिया के साथ भारत का कुल व्यापार 1 ट्रिलियन से अधिक का था, जो निर्यात के साथ वित्तीय वर्ष में पहली बार 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया था। भारत विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। इससे व्यापार और निवेश के प्रवाह में भी वृद्धि होगी।

दूसरा, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण वित्तीय बाजारों के विकास को बढ़ावा देगा। एडीबी के एक अध्ययन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य बताते हैं कि व्यापार निपटान के संदर्भ में मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण का वित्तीय बाजार के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक इकाई की वृद्धि से वित्तीय बाजार के विकास में निजी ऋण के मामले में 0.2 प्रतिशत अंक और शेयर बाजार के कुल मूल्य के मामले में 0.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि होने की संभावना है।

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे पहले बढ़े हुए व्यापार और एफडीआई प्रवाह के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी एकीकरण को बढ़ाएगा।

– अनिल तिवारी

तीसरा, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण वित्तीय संस्थानों के लिए मुद्रा बेमेल को कम करने में सहायक होगा। चौथा, भारत उच्च व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 102.63 बिलियन डालर की तुलना में बढ़कर 192. 21 बिलियन डालर तक पहुंच गया है। इस तेजी से बढ़ती वृद्धि का प्राथमिक कारण प्रमुख वस्तुओं के आयात विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रमुख आयातो के लिए रुपए का उपयोग करने से व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

पांचवा, रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए नीतिगत निर्णय अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। नेपाल और भूटान के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को पहले भी रुपए का उपयोग करके आधिकारिक तौर पर संचालित करने की अनुमति दी गई थी। भौगोलिक निकटता कारणों के अलावा इस ने भारत को इन दोनों देशों के लिए सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरने में भी मदद की थी। यह कदम अब रुपए को सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ

अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देगा, और क्षेत्र में भारत की प्रमुख स्थिति को बहाल करने में मदद करेगा।

लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए रुपए को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और इसे दुनिया के लगभग सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन के लिए पसंद की मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है।

इस क्रम में हमें अमेरिकी डालर के वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकृति और उसके दबदबे को समझने की सख्त जरूरत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं, लेकिन सभी देशों के केंद्रीय बैंकों में जमा कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 64 प्रतिशत अमेरिकी डालर है। दुनिया के संपूर्ण व्यापार का 85 प्रतिशत व्यापार आज भी डालर में होता है। संसार के समस्त कार्यों में डालर की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत के आसपास है। यही कारण है कि अमेरिकी डालर दुनिया की सबसे स्वीकारी मुद्रा बनी हुई है।

वैसे तो अर्थशास्त्र का एक सामान्य नियम है कि अगर किसी देश की मुद्रा मजबूत होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर कई एक नकारात्मक असर पड़ता है, लेकिन अमेरिका के मामले में इसका उलट होता है। जैसे ही अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है वैसे ही तमाम वैश्विक निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वापस लौट आते हैं। डालर के मजबूत होने से उनका आयात सस्ता हो जाता है जिससे सामान्य उपभोग की चीजें सस्ती हो जाती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत हिस्सा उपभोग पर आधारित है। हालांकि दुनिया को कई बार इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, जैसे वर्ष 2008 में अमेरिका की स्थानीय नीतियों के कारण आई मंदी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद चीन और रूस जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डालर के वर्चस्व को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया था।।

बाद में चीन और रूस ने अपना आपसी व्यापार अपनी अपनी मुद्रा में शुरू कर दिया। रूस के केंद्रीय बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली तिमाही में रूस और चीन के बीच व्यापार में डालर की हिस्सेदारी पहली बार 50 प्रतिशत के नीचे चली गई जो कि वर्ष 2015–16 में 90 प्रतिशत थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तब भी चीन रूस का व्यापार यथावत जारी रहा। हाल के वर्षों में जब हमारा सामना कोविड–19, विश्व आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुई आर्थिक उथल–पुथल से हुआ तब भारत के नीति निर्माताओं ने भी देश के आर्थिक हितों के संबंध में सोचने पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी रूप में एकाधिकारी प्रवृत्ति या किसी भी आपूर्ति के लिए एक देश पर निर्भरता भारत के या किसी भी देश के दीर्घकालिक हितों के प्रतिकूल है। किसी देश की मुद्रा की कीमत के निर्धारण में उसके आयात निर्यात के आकार, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन और वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का हाथ होता है। हाल में डालर की तुलना में रुपया भले ही कमजोर हुआ है लेकिन अन्य मुद्राओं की अपेक्षा सबसे कम गिरा है। जापानी येन, चीनी युआन सहित अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपया मजबूत ही हुआ है। अभी एक अमेरिकी डालर के बदले 138 जापानी येन मिल रहा है जबकि 2018 में 110 येन मिलते थे। वहीं 2007 में एक यूरो के बदले 1. 6 डालर मिलता था जबकि आज एक यूरो 1 रूपये के बराबर हो गया है। भारतीय रुपए की मजबूती का कारण भारत में राजनीतिक स्थिरता, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्वों का मजबूत होना और मुद्रास्फीति के बावजूद भारत में लगातार मांग का बने रहना है। भारत आज विश्व की सर्वाधिक तेजी के साथ रिकवरी करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल है। यह कहा जा सकता है कि आगामी वर्षों में जैसे–जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी वैसे वैसे भारतीय रुपया भी मजबूत हो सकता है।

अब आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने निर्णय को वैश्विक स्तर पर लागू करवाने की होगी। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर भारतीय बैंकों की वैश्विक उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। कारोबारी देश के केंद्रीय बैंकों से समायोजन करना होगा। रुपए में लेनदेन के लिए देश के आयातकों और निर्यातकों को किसी भी व्यवसायिक बैंक में खाता खोलना होगा। फिर रुपए का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य पर निर्धारित करते हुए उस देश की मुद्रा में सीधे हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसका तात्कालिक लाभ भारत को ईरान रूस के साथ उन देशों के साथ व्यापार में भी मिलेगा जिनके पास या तो अमेरिकी डॉलर नहीं है या जो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। भारत अपनी आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत तेल और गैस आयात करता है इसलिए रुपए में व्यापार से भारत लाभ की स्थिति में होगा। कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्णय से भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और लगातार बढ़ रहे कद के कारण रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करने में मदद मिल सकती है। ❑❑

उद्यमिता, स्वरोजगार व स्वावलम्बन

उद्यमिता, स्वरोजगार और सहकारिता अनादिकाल से भारतीय–समाज जीवन व अर्थतंत्र का मूल आधार रहा है। इसीलिए ब्रिटिश शासन में 1835 में भारत के कार्यकारी गवर्नर जनरल रहे चार्ल्स टी मेटकॉफ ने प्रत्येक भारतीय ग्राम को ही ''स्वावलम्बी लघु गणराज्य'' कहा है। अनादिकाल से ही भारत उन्नत कृषि व उद्यमिता का केन्द्र रहा है। ब्रिटिश आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मेडिसन के अनुसार 15वीं सदी तक तो विश्व के कुल उत्पादन में भारत का 34 प्रतिशत योगदान रहा है। इसी कारण मत्स्य पुराण सहित विविध प्राचीन ग्रन्थों में भारत को ''विश्व का भरण–पोषण करने में सक्षम राष्ट्र'' कहा गया है। प्राचीन काल से हुए देश के अनेक विभाजनों के बाद भी आज भारत के पास सर्वाधिक 18 करोड़ हेक्टर कृषि योग्य भूमि है। विश्व की कार्यशील आयु की सर्वोच्य जन शक्ति भारत में है। विश्व के सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों से युक्त राष्ट्र होने से भारत आज विश्व में सर्वाधिक द्रुत आर्थिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था है। देश में आज 9 करोड़ सूक्ष्म लघु व मध्यमाकार उद्यम हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक युवा–शक्ति युक्त देश होने से आज कार्य करने की आयु के सभी व्यक्तियों को यथोचित आय–युक्त कार्य या रोजगार में लगाया जाना परम आवश्यक है।

रोजगार – भारतीय पारंपरिक चिंतन का आधार

भारत अनादि काल से विकेन्द्रित उद्यमों का केन्द्र व पूर्ण रोजगार युक्त देश रहा है। प्राचीन काल में भी हमारे देश में सम्भूव समुत्थान, सम्वितान आदि कई नामों से सहकारी व साझेदारी व्यवसाय भी रहे हैं। आज भी भारत विश्व का तीसरा प्रमुख स्टार्ट–अप का परिस्थितिकी तंत्र है। रामायण काल में राजा दशरथ के अर्थशास्त्री रहे उपाध्याय सुधन्वा से लेकर चाणक्य तक सभी प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने कार्य करने में सक्षम प्रत्येक व्यक्ति को वृत्ति युक्त किए जाने पर बल दिया है। कार्य करने में सक्षम प्रत्येक व्यक्ति को वृत्ति अर्थात रोजगार में संलग्न करने के सम्बन्ध में 'उपाध्याय सुधन्वा का कथन कि राज्य में निवासरत व कार्य करने में सक्षम प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित कार्य में संलग्न करना, उस कार्य से उसे समुचित आय की प्राप्ति होना, उस आय का सतत विवर्धन और उसके सम्यक वितरण परम आवश्यक है। अर्थशास्त्र के इसी प्राचीन सिद्धान्त का प्रतिपादन कर चाणक्य ने भी लिखा है कि मनुष्यों को वृत्ति अर्थात रोजगार से युत करना ही अर्थशास्त्र है (मनुष्याणां वृत्ति अर्थः)। संस्कृत शब्द वृत्ति का अर्थ रोजगार होता है।

स्वावलम्बन से 400 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनना संभव

भारत की वर्तमान 142 करोड़ जनसंख्या आज सम्पूर्ण यूरोप के 50 देशों व लेटिन अमेरिका के 26 देश अर्थात विश्व के कुल 76 देशों की सम्मिलित जनसंख्या से अधिक है। उपरोक्त 142 करोड़ जनसंख्या में आज 90 करोड़ लोग 15–64 वर्ष के बीच कार्यशील आयु सीमा में हैं। वर्ष 2030 तक कार्यशील आयु की जनसंख्या 100 करोड़ हो जाएगी। यह विश्व की कार्यशील आयु की जनसंख्या का 24.3 प्रतिशत होगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ व अन्य कई अर्थशास्त्रियों के आकलनों के अनुसार यदि देश की सम्पूर्ण कार्यशील आयु की जनसंख्या रोजगार युक्त हो जाये तो भारत 40 ट्रिलियन डालर अर्थात 400 खरब डालर या 32,800 खरब रूपये की अर्थव्यवस्था बन सकता है।

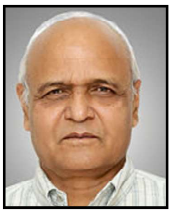

स्वावलम्बी भारत अभिमान के अन्तर्गत देश में बड़ी संख्या में जिला रोजगार सृजन केन्द्रों की स्थापना हुई है। ये जिला रोजगार सृजन केन्द्र युवाओं में उद्यमिता का भाव जागरण करने, उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देने और नवीन उद्यम स्थापित करने के कार्य में सहयोग प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

वर्तमान में भारत की सकल राष्ट्रीय आय अर्थात सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.2 ट्रिलियन डालर है। इस प्रकार कार्यशील आयु के सभी लोगों को रोजगार या स्वरोजगार में यथोचित रूप से नियोजित कर लेने से भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक 12 से 13 गुना विस्तार पा सकेगी। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के छः दशक पुराने इस वक्तव्य कि ''हर हाथ को काम'' की आज भी वही सार्थकता है। सर्वाधिक बेरोजगारी आज शिक्षित वर्ग में है। उद्यमिता ही बेरोजगारी निवारण का साधन बन सकती है। इसलिए शिक्षा के साथ उद्यमित विकास को जोड़ा जाना आवश्यक है।

सूक्ष्म व लघु उद्यम

देश में आज विश्व के सर्वाधिक 9 करोड़ सूक्ष्म व लघु उद्यम हे। कार्यशील आयु के सभी व्यक्तियों को कार्य में संलग्न करने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यम ही प्रभावी साधन हैं। भाव जागरण, उद्यमिता प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन व सहकार–पूर्वक युवाओं को अपना काम स्वयं आरम्भ करने की दिशा में अग्रसर करने से ही यह संभव होगा। इस दृष्टि से कार्यशील आयु के प्रत्येक व्यक्ति को अपना उद्यम प्रारम्भ करने की दिशा में प्रेरित किया जाना आवश्यक है।

ग्रामोद्योग व ग्राम स्वावलम्बन

ग्रामीण कृषि उत्पादों व अन्य वस्तुओं के मूल्य संवर्द्धन हेतु ग्रामोद्योगों की स्थापना से ही देश में व्यापक समृद्धि सम्भव हैं। यदि किसान गेहूँ की बिक्री के स्थान पर उससे आटा, मैदा, सूजी, बिस्किट, ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि के उत्पादन हेतु ग्रामोद्योग की स्थापना करेंगे, तब ही उनकी प्रगति सम्भव है। इसी प्रकार सभी कृषि उत्पादों व लघु वन उपज आदि के मूल्य संवर्द्धन के लिए ग्रामीण उद्योग लगाए जाने से ग्राम रोजगार बढ़ेगा व गांवों में समृद्धि आएगी। इस हेतु ग्रामीण समुदायों को उद्यमिता व उत्पादन कौशल में प्रशिक्षित किया जाना होगा। देश की समग्र कृषि योग्य 18 करोड़ हेक्टर भूमि में सिंचाई के साथ भारत विश्व की दो तिहाई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति कर सकता है। विश्व के सर्वाधिक जैविक कृषिकर्त्ता किसान भारत में हैं। ऐसे में देश के ग्रामीण युवा जैविक कृषि उपज के मूल्य सवंद्धित उत्पाद तैयार कर उनका निर्यात कर सकते है। रसायन रहित जैविक खाद्य उत्पादों की पूरे विश्व में भारी मांग है। इसलिए देश में फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन की स्थापना की गति बढ़ाई जानी चाहिए। गैर कृषि ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि से इतर उत्पादक संगठनों के भी द्रुत प्रवर्तन की आवश्यकता है।

स्टार्टअप

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप ईकोसिस्टम है। देश में 50 से अधिक स्टार्ट–अप संवर्द्धन की शासकीय योजनाएँ भी हैं। देश के युवा नई अवधारणा आधारित अनेक व्यवसाय कर उन्हें यूनिफार्म में संवर्धित कर सकते हैं। जब किसी स्टार्टअप का बाजार पूंजीकरण 1 अरब डालर पार कर जाता है तो वह यूनिकॉर्न कहलाता है। देश में आज 108 यूनिकॉर्न हैं जिनका बाजार मूल्य 345 अरब डालर है।

स्वावलम्बी कैसे बनें

भारत जैसे विशाल देश में जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध नौकरियों संख्या अत्यन्त सीमित है। आज केवल 7.3 प्रतिशत जनता आज सरकारी या किसी सुसंगठित प्रतिष्ठान में नियोजित है। शेष सभी लोगों को अपने स्तर पर किसी स्वरोजगार में लगना अर्थात अपन स्वयं का कोई उद्यम स्थापित कर स्वावलम्बी बनना चाहिए।

किसी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। सूक्ष्म वित्त के माध्यम से या प्रधानमंत्री मुद्रा के माध्यम में से किसी लघु व्यापारिक, उत्पादन, सेवा सम्बन्धी व्यवसाय की स्थापना करके कोई भी स्वावलम्बी बन सकता है। स्टार्ट–अप प्रारम्भ करके, आगे बढ़ा जा सकता है। कृषक उत्पादक संगठन, गैर कृषि उत्पादक संगठन बना कर, कोई सहकारी संस्थान बना कर या और भी किसी प्रकार से व्यवसाय प्रारम्भ करके समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अपना काम प्रारम्भ कर व्यक्ति स्वयं के लिए अर्थ उपार्जन के साथ अन्य लोगों के लिए भी अन्य लोगों को भी उसमें नियोजित कर रोजगारदाता बन सकते हैं।

इस संबंध में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु स्वावलम्बी भारत अभियान द्वारा स्थापित किसी रोजगार सृजन केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि की सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। स्वावलम्बी भारत अभिमान के अन्तर्गत देश में बड़ी संख्या में जिला रोजगार सृजन केन्द्रों की स्थापना हुई है। ये जिला रोजगार सृजन केन्द्र युवाओं में उद्यमिता का भाव जागरण करने, उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देने और नवीन उद्यम स्थापित करने के कार्य में सहयोग प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। स्वावलम्बी भारत अभियान के ही अन्तर्गत देश में 45 प्रान्तों की रचना कर, ऐसे प्रत्येक प्रान्त में और सभी जिलों में स्वावलम्बी भारत अभियान की टोलियाँ, उद्यमिता विकास के कार्य में पिछले एक वर्ष से सक्रिय है। देश भर के आज 30 से अधिक राष्ट्रव्यापी संगठन इस अभियान को दिशा व गति प्रदान कर रहे हैं। देश में प्रत्येक कार्य करने की आयु का व्यक्ति रोजगार युत हो, इस महान लक्ष्य के साथ आज **स्वावलम्बी भारत अभियान** सक्रिय है। ❑❑

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) कितना उपयोगी?

विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाती संभावनाओं का अशुभ संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व अर्थव्यवस्था 2023 से 2030 के बीच प्रतिवर्ष 2. 2 प्रतिशत के हिसाब से तीन दशक के निचले स्तर तक गिरने की संभावना है। हालांकि यह आंकड़ा 2011–2021 के 2.6 प्रतिशत और 2001–2011 में 3.5 प्रतिशत से कम है। इसमें तत्कालिक कारणों के अलावा कोविड–19, युद्ध, कमोडिटी की कीमतें, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से पूंजी संचय, श्रम शक्ति में वृद्धि या श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण गंभीर रूप से नुकसान हुआ है। वर्तमान दशक के शेष वर्षों के दौरान इन सभी मोर्चों पर और धीमे होने की संभावना है। अनुमान किया गया है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संकट आने या वैश्विक मंदी शुरू होने पर संभावित विकास दर नकारात्मक रूप से और अधिक प्रभावित हो सकती है।

धीमी विकास दर सबके लिए घातक होती है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से हानिकारक मानी जाती है। हालांकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अपने समूह में भारत अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर हो सकता है लेकिन भू राजनीतिक तनाव, व्यापार के लिए खुलापन का कम होना, नीति की अनिश्चितता और इसी तरह के अन्य कारण भारत के लिए अपने वांछित विकास पथ पर चलना उतना सरल नहीं रह जाएगा। उदाहरण के लिए भारत के निर्यात की मांग, जो घरेलू विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है, के कमजोर रहने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। सरकार इसे मुक्त व्यापार समझौतों, आयात प्रतिस्थापन, आयात विविधीकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, लचीला तथा व्यापार सुगम, वित्तीय संस्थान जैसे अन्य उपायों के माध्यम से हासिल करने की उम्मीद करती है। कोविड–19 के बाद पूरी दुनिया भारत को चीन के विकल्प के रूप में आजमाने की कोशिश भी कर रही है और भारत का लक्ष्य भी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भागीदार बनने की है। यह अच्छी बात है और इसके लिए सरकार के स्तर पर पहल भी हो रही है।

दुनिया के बाजार में मुक्त व्यापार समझौते का माहौल है। भारत दुनिया में तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, भारत की प्रगति दुश्मन देशों को फूटी आंख भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे में हमें एफटीए के मोर्चे पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है।

– के.के. श्रीवास्तव

लेकिन हम अप्रिय तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते। नोबेल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव के अनुसार भारत का व्यापारिक आयात 2023 में 15 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 710 बिलियन डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। वास्तव में भारत का आयात इसके 25 व्यापारिक भागीदारों में से 22 के निर्यात से अधिक है। भारत की दिली इच्छा के बावजूद चीन भारत का सबसे बड़ा आयात का स्त्रोत भी बना हुआ है, जिसका भारत के विरुद्ध 87.5 बिलियन डालर का प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच 'चाइना प्लस वन' रणनीति का अनुसरण करने की प्रवृत्ति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहा है, जो भारत वैकल्पिक स्थलों की खोज करके चीन में विनिर्माण उत्पादन पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसके बजाय वियतनाम, थाईलैंड आज छोटे देश आगे बढ़ गए हैं। संसाधनों और योजना की उपलब्धता के बावजूद चीन से दूर जा रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश में स्थानांतरित करने में अभी तक विफल ही रहा है। हालांकि भू राजनीतिक घटनाओं उच्च कीमतों आपूर्ति में व्यवधान आदि के कारण कमजोर वैश्विक मांग के समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था मामूली रूप से प्रभावित होगी, फिर भी इसके निर्यात पर प्रतिकूल असर होने की संभावना है।

दो देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए पारंपरिक व्यापार के दायरे

से बाहर निकलकर मुक्त व्यापार समझौते की बात की गई। संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जीसीसी और यूरोपीय संघ सहित कई एक देश भारत के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने को इच्छुक हैं। बहुत अच्छी और द्विपक्षीय दोनों स्तरों पर भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि के परिणाम के रूप में भारत विभिन्न देशों के बीच संबंधों के इस बड़े हुए स्तर पर क्षमता से देख रहा है। भारत एक मध्यम आय वाला देश बनने की अपनी खोज में विभक्ति बिंदु पर पहुंचने के कगार पर है, जो कि चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का आर्थिक दबदबा बढ़ रहा है और बाहरी आर्थिक संबंधों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार के प्रति कुछ अनूठा दृष्टिकोण अपनाने का फैसला भी किया है। प्रोडक्शन लिंकड इनसेटिंव (पीएलआई) योजना इसका एक उदाहरण है। हालांकि समग्र रूप से विश्व वैश्विक स्तर पर एकीकरण से पीछे हट रहा है और भारत इस तथ्य को जानता है। हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपनी विशाल घरेलू अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए भारत ने संभलकर चलने का फैसला किया है। यही कारण है कि हमारी बाजारों को पूरी तरह से खोलने के बजाय अन्य बातों के साथ–साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया गया है। हालांकि इस तरह के समझौते के लिए आगे आने वाला भारत अकेला देश नहीं है।

सामान्य धारणा है कि एफटीए व्यापार बढ़ाने का एक उम्दा मंच है। आज दुनिया भर में 350 से अधिक एफटीए हुए हैं जो वर्तमान में लागू हैं। आर्थिक विकास के लिए एफटीए को सौ ताले की एक चाबी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश को इस

सामान्य धारणा है कि एफटीए व्यापार बढ़ाने का एक उम्दा मंच है। आज दुनिया भर में 350 से अधिक एफटीए हुए हैं जो वर्तमान में लागू हैं। आर्थिक विकास के लिए एफटीए को सौ ताले की एक चाबी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

मोर्चे पर ठहर कर सोचना चाहिए और फिर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी के जाल में फंसने की वजाय कुछ जरूरी तथ्यों पर ध्यान देते हुए सावधान कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

1. विकसित देश एफटीए पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं या छोटे देशों के साथ एफटीए करने में बहुत चयनात्मक हैं।

2. यह जरूरी नहीं कि एफटीए करने से निवेश को बढ़ावा मिल जाएगा। निवेश की गुणवत्ता आमतौर पर दक्षता पर निर्भर करती है। एक देश जो अधिक कुशल है, उसके विनिर्माण केंद्र बनने की संभावना है, न कि केवल एफटीए पर हस्ताक्षर करने के कारण।

3. आसियान को भारतीय निर्यात का 70 प्रतिशत एमएफएन पर प्रवेश मिलता है, एफटीए के कारण नहीं। इसलिए कई बार एफटीए के माध्यम से होने वाले व्यापार को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जाता है।

4. आवश्यक रूप से कीमतों को कम नहीं करते हैं यदि सभी कीमतों को केवल उस सीमा तक कम किया जा सकता है कि निर्यातक घरेलू फर्म से प्रतिस्पर्धा को दूर कर सके।

5. मार्ग के माध्यम से माल तैयार माल का शून्य शुल्क आयात वास्तव में बढ़ावा देने के बजाय कई घरेलू विनिर्माण कार्यक्रमों को बाधित कर सकता है। इसलिए तैयार माल के आयात के इस मुद्दे को और अधिक सावधानी से देखने की जरूरत है।

6. कई विकसित देश बड़ी आसानी से विकासशील देशों से विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के साथ–साथ बौद्धिक संपदा पर्यावरण आदि मुद्दों के दायित्वों का पालन करने के लिए कहते हैं। विकासशील देशों के निर्यात के खिलाफ कई गैर टैरिफ बाधाएं लगाई जाती है।

7. यदि हमारे साझेदार देश का शेष विश्व के लिए वैसे भी कम आयात शुल्क है, तो हमें शायद ही भारत से एफडीए भागीदार देशों को निर्यात में त्वरित वृद्धि देखने को मिले।

8. वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बढ़ी हुई भागीदारी का नेतृत्व कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि एफटीए के तहत मूल शर्तों के नियमों का अनुपालन होना चाहिए, शून्य एमएफएन शुल्क के तहत माल की मुक्त आवाजाही सबसे अच्छा है।

सवाल है कि क्या हमें एफडीए पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए? नहीं, इसके बजाय हमें और अधिक गणनात्मक होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें वियतनाम से सीखने की जरूरत है, जो व्यापार सृजन पर ध्यान केंद्रित करता है न कि व्यापार मोड पर। इस प्रकार भारत को निर्यात करने वाले देशों के लिए एक विनिर्माण गंतव्य बनना चाहिए जो यहां आधार स्थापित करते हैं और तैयार माल को विकसित बाजारों के साथ–साथ अन्य देशों में निर्यात करते हैं। दूसरे शब्दों में इसका लक्ष्य मूल्य संवर्धन के अधिक से अधिक हिस्से पर कब्जा करना होना चाहिए। वर्तमान में अलग–अलग एफटीए का हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ा है, इसलिए हमें आगे संभलकर चलने की जरूरत है। ❑❑

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ मंगल संकेत

इस समय की दुनिया हाई इंट्रेस्ट रेजीम यानी उच्च ब्याज दर की व्यवस्था में चल रही है। अमेरिका में ब्याज दर 2007 के बाद से अब तक सबसे अधिक है। वहां ब्याज दर 5 फीसदी से अधिक हो गई है जबकि मार्च 2018 में केवल डेढ़ प्रतिशत थी। यानी पांच साल में 300 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह ब्रिटेन में मौजूदा ब्याज दर 4.25 प्रतिशत है जो कि पांच साल पहले एक प्रतिशत से भी कम थी। यानी पांच साल में लगभग 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

फ्रांस में ब्याज दर 3.5 प्रतिशत है जो कि पांच साल पहले 2018 में 0.65 प्रतिशत थी। यहां भी पांच साल में 5 गुणा ब्याज दर में बढ़ोतरी हो गई है। जर्मनी में भी ब्याज दर पांच साल में एक फीसदी से भी कम से बढ़कर आज 3.5 प्रतिशत है। जबकि भारत में ब्याज दर में पिछले पांच साल में केवल 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2018 में भारत में बैंक ब्याज दर 4 प्रतिशत थी जो कि इस समय 6.5 प्रतिशत है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि ये सारे आंकड़े इन सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित हैं।

ये वही देश हैं जिनके साथ हमारी अर्थव्यवस्था का आंकलन किया जाता है। हां अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है, जहां ब्याज दरों की बढ़ोतरी पर बहुत हद तक अंकुश है। चीन ने वर्षों से बैंक ब्याज दर को 3.5 प्रतिशत के आस पास बनाए रखा है।

यदि एशियाई देशों में लागू बैंक ब्याज दर देखें तो भारत लगभग सभी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा स्थिर है। इस समय म्यांमार में 7 प्रतिशत, नेपाल में 8.5 प्रतिशत, पाकिस्तान में 21 प्रतिशत और श्रीलंका में 15.5 प्रतिशत बैंक ब्याज दर है। यह सामान्य सी बात है कि बैंक ब्याज दर में स्थिरता या न्यूनतम भटकाव ना सिर्फ मजबूत अर्थव्यवस्था का द्योतक है, बल्कि सिस्टम में आवश्यक साख की आपूर्ति भी है। भारत के आंकड़े हमें निश्चितता प्रदान करते हैं। 6 अप्रैल को जारी मौद्रिक नीति में ब्याज दर में किसी भी वृद्धि की घोषणा नहीं होना और सुकून देता है।

महंगाई, रूपये के अवमूल्यन, बेरोजगारी और राज्यों की खराब आर्थिक सेहत विकास की कहानी में कुछ सवालों को जन्म जरूर देती हैं लेकिन मंदी से रूबरू हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति बहुत से देशों से बेहतर दिखती है।

–विक्रम उपाध्याय

जबर्दस्त जीएसटी संग्रह

अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने का एक आधार कर संग्रह भी है। इस मार्च में एक लाख 60 हजार करोड़ का रिकार्ड जीएसटी संग्रह बताता है कि भारत का व्यावसायिक वर्ग किसी मंदी के अंदेशे या किसी अस्थिरता की आशंका से ग्रसित नहीं है। उसे भारत की अर्थव्यवस्था और सरकार दोनों पर भरोसा है। इस साल चौथी बार जीएसटी संग्रह डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा रहा। अन्य करों का संग्रह भी लगातार बढ़ रहा है। फिर भी यह कहना ठीक नहीं है कि कर जीडीपी का हमारा अनुपात काफी ठीक है। भारत का टैक्स जीडीपी अनुपात 7.8 है, जबकि चीन का 12.6 प्रतिशत। अमेरिका और यूरोप में टैक्स जीडीपी अनुपात 18 से 25 प्रतिशत तक है। यानी रिकार्ड कर संग्रह होने के बावजूद अभी हम कई देशों से पिछड़े हैं।

जीडीपी ग्रोथ में भारत अव्वल

इस समय पूरी दुनिया में अकेले भारत ही है जिसका जीडीपी ग्रोथ 6 प्रतिशत से अधिक है। चीन अभी भी 5 प्रतिशत से अधिक जीडीपी ग्रोथ का दावा नहीं कर रहा है। बाकी देशों में विकास दर दो से तीन प्रतिशत को काफी माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022–23 में भारत में जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहेगी, जबकि विश्व बैंक ने अनुमान घटाकर इसे 6.3 प्रतिशत कर दिया है। किसी ने भी जीडीपी वृद्धि दर में 6 प्रतिशत से कम का आकलन नहीं किया है।

विदेशी मुद्रा भंडार

मंदी की आहट और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से कई देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन हम डॉलर के संदर्भ में करते हैं और अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों के मुद्रा भंडार को हम उसकी

विदेशी मुद्रा भंडार को एक मजबूत स्थिति में बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने रूस के साथ तेल खरीद का जो करार किया है, उसका भी योगदान बहुत है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है।

अर्थव्यवस्था की मजबूती के आधार के रूप में देखते हैं। चीन के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का भंडार है, लगभग 3315 बिलियन डॉलर। अमेरिका के साथ व्यापारिक पंगा और अन्य कई देशों द्वरा चीन के बहिष्कार के कारण पिछले एक साल में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में 57 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। लेकिन भारत औसत 580 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ स्थिर है। यानी भारत के प्रति विदेशी निवेशकों का विश्वास बना हुआ हैं। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार को एक मजबूत स्थिति में बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने रूस के साथ तेल खरीद का जो करार किया है, उसका भी योगदान बहुत है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है।

महंगाई की मार बेअसर

कोविड प्रकोप ने पूरी दुनिया की मांग–आपूर्ति की व्यवस्था को पहले ही ध्वस्त कर दिया था। रही सही कसर रूस –यूक्रेन युद्ध ने पूरी कर दी। दुनिया भर में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हां भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल है, जिसने ना सिर्फ महंगाई को बेलगाम होने से रोका है, बल्कि देश के 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराकर गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का एक अनोखा काम किया है।

आईएमएफ द्वारा हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व भर में महंगाई की दर 6.6 प्रतिशत रहने वाली है। आईएमएफ ने चीन, जापान और ताईवान के बाद भारत के बारे में ही यह भविष्यवाणी की है कि यहां महंगाई को निरूपित करने वाली मुद्रा स्फीति की दर 5.1 प्रतिशत रहेगी। बाकी 50 से अधिक देश हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, जहां महंगाई की दर 9 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक हो सकती है।

इस सूची में हमारे दो पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हैं। फिर भी भारत में महंगाई महसूस की जा रही है। यह आर्थिक के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दा भी है जिसका जवाब सरकार को देना है।

सकारात्मक संकेत

कुछ बेहद सकारात्मक संकेत हैं जिनसे यह लगता है कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। जैसे– बेरोजगारी की दर 7.8 से घटकर 7.5 प्रतिशत पर आ गई है। लोगों का बिजनेस कांफिडेंस बढ़ा है। बैंकों की सेहत काफी सुधर चुकी है। जमा और कर्ज उठाव दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सेवा क्षेत्र के बिजनेस में 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है और सबसे बड़ी बात कि कृषि उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुई है। सरकारी आकड़ों के अनुसार 2022–23 में 3235.54 लाख टन अनाज की पैदावार हुई है। हमें खुश होना चाहिए कि हम खुद भी खा सकते हैं और दुनिया के कई देशों को खिला रहे हैं।

महंगाई, रूपये के अवमूल्यन, बेरोजगारी और राज्यों की खराब आर्थिक सेहत विकास की कहानी में कुछ सवालों को जन्म जरूर देती हैं लेकिन मंदी से रूबरू हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति बहुत से देशों से बेहतर दिखती है। ❑❑

उच्च शिक्षा के मोर्चे पर बेहद सावधानी की जरूरत

वर्ष 2020–21 के दौरान उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों का नामांकन 4.1 करोड़ तक पहुंच गया। यह वर्ष 2019–20 से 7.5 प्रतिशत और वर्ष 2014–15 से 2.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सकल नामांकन अनुपात भी 27.3 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इसमें महिलाओं का नामांकन 2.1 करोड़ था। वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में 70 प्रतिशत नए विश्वविद्यालय तथा 1453 नए कालेज जोड़े गए थे। देश में कुल 1043 उच्च शिक्षण संस्थान है, जिनमें 184 केंद्रीय वित्त पोषित है, जबकि बाकी राज्य पोषित है।

विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा भारत एक ज्ञानी समाज के रूप में अपनी उपस्थिति चाहता है, लेकिन शिक्षा में निवेश की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। भारत शिक्षा पर औसतन अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.9 प्रतिशत ही खर्च करता है। भारत की प्राथमिकताएं उलझी हुई हैं। निवेश के मामले में शिक्षा, यहां तक कि स्वास्थ्य और पोषण का भी बुरा हाल है। हालांकि यह सभी जानते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का निवेश परम आवश्यक होता है। क्योंकि व्यापक शिक्षा न केवल हमारी समग्र समृद्धि में इजाफा करती है बल्कि अमीरों और वंचितों के बीच मौजूद खाई को पाटने में भी मदद करती है। बावजूद व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य कभी भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं हासिल कर सका है। समय के साथ समाज में हुए परिवर्तनों के कारण भी शिक्षा की उपेक्षा होती रही है। नव–उदारवादी दौर आने के साथ ही राज्य धीरे–धीरे लोक कल्याण के मामलों से पीछे हटते गए और शिक्षा का अधिकाशत निजीकरण होता गया। अब भारत में भी विदेशी विश्वविद्यालयों को निमंत्रण दिया जाना, इसका जीता जागता उदाहरण है।

शिक्षा को किसी भी रूप में एक निजी बसतु नहीं माना जा सकता इसके बजाय इसे योग्यता वस्तु के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राज्य सभी पढ़ने योग्य विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली विश्वविद्यालय प्रणाली प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता।

– डॉ. जया कक्कड़

कई एक अर्थशास्त्री शिक्षा को सार्वजनिक वस्तु के रूप में देखते हैं। जिसमें बहुत सारी सकारात्मक बाहरीताएं होती है, या कम से कम योग्यता वस्तु (यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी आपूर्ति बाजार के माध्यम से की जा सकती है लेकिन समाज के सर्वोत्तम हित में अतिरिक्त लाभप्रदता के हिसाब से इसे सार्वजनिक वस्तु के रूप में प्रदान किया जाता है)। लेकिन भारत में अभी भी शिक्षा निजी वस्तु के रूप में माना जाता है। मानकीकृत, कमोडिटीकृत पैकेज्ड और मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों के आधार पर बेचा जाता है। जिनके पास क्रय शक्ति नहीं है वह अच्छी शिक्षा की पहुंच से बहुत दूर है। यही कारण है कि भारत में एक ओर निजी घरेलू विश्वविद्यालयों, जिनमें जिंदल, शिव, नाडर, अशोक और कई अन्य शामिल हैं, को लगातार आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, वहीं विदेशी विश्वविद्यालयों को आने और अपनी पेशकश करने के लिए खुला निमंत्रण भी सौंपा गया है।

तथ्यात्मक रूप से भी शिक्षा कोई समरूप विचार नहीं है, जिन्हें समान, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ किसी भी मिट्टी पर आयात किया जा सकता है। समान विचार की धारणा ही असत्य है। अगर ब्रिटेन, अमेरिका का कोई विश्वविद्यालय भारत आता है तो क्या वह दादा भाई नौरोजी या किसी आरसी दत्त के कार्यों को अपने विद्यार्थियों के बीच पढ़ायेगा? क्या ऐसे विश्वविद्यालय इस स्थापित दृष्टिकोण से सहमत होंगे कि अल्प विकास का साम्राज्यवाद से संबंध है? उपनिवेशवाद तो संभवत पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं होगा? यहां तक कि विज्ञान के क्षेत्र में भी क्योंकि हमारी अपनी अनूठी समस्याएं हैं

(पानी स्वच्छता सस्ती बिजली प्रदान करना आदि)। ऐसे में हमारे पाठ्यक्रम की सामग्री को विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जगह क्या मिल सकती है? इसका उत्तर होगा, नहीं। और आवश्यक रूप से यह विश्वविद्यालय अपना अलग पाठ्यक्रम लेकर आएंगे। अगर हम अपने प्राचीन के अद्‌भुत ज्ञान के बल पर वैदिक गणित, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद जैसी विद्या का मोती पा रहे हैं तो सवाल है कि क्या यह विदेशी विश्वविद्यालय इन्हें अपने शिक्षण का हिस्सा बनाएंगे? निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं। ऐसे में हमें हर हाल में तृतीयका स्तर सहित बेहतर सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकता को मुखर करने की जरूरत है।

अगर हम उच्च शिक्षण संस्थानों की एचईआई के नेशनल इंशुरंस रैकिंग फ्रेमवर्क रैकिंग को देखें, तो पाते हैं कि ज्यादातर भारतीय विश्वविद्यालय बेहद खराब प्रदर्शन करते हैं। खासकर राज्य द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थान। राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण है, उनकी खराब वित्तीय स्थिति। राज्यों के द्वारा संचालित हो रहे विश्वविद्यालय बहुत खराब शैक्षणिक और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे से पीड़ित हैं। पठन–पाठन से लेकर संसाधनों तक की स्थिति बहुत ही निचले दर्जे की हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। यहां एक एक कक्षा में 100 से 150 छात्र तक हो जाते हैं जबकि आदर्श रूप में एक कक्षा में 50 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। देश के अधिकांश विश्वविद्यालय स्वाभाविक रूप से संकाय शक्ति, शिक्षक छात्र अनुपात, सीखने के संसाधन, भौतिक आधारभूत संरचना सहित खराब अकादमिक प्रदर्शन संकेतक होने से पीड़ित है। इसकी सूची अंतहीन है। उच्च शिक्षण संस्थानों की खराब स्थिति के कारण देश से अच्छी शिक्षा की चाह में लगातार प्रतिभा का पलायन हो रहा है और इसके चलते भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में हमें अपनी प्रतिभा को रोकने तथा अपने विश्वविद्यालयों की दशा–दिशा ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हम त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पर विदेशी विश्वविद्यालय जब आएंगे जिन्हें अपने स्वयं के कर्मचारियों को अपनी शर्तों पर नियुक्त करने और अपने स्वयं के पाठ्यक्रम को तैयार करने की लगभग पूर्ण स्वतंत्रता होगी। वह निश्चित रूप से अपनी प्रवेश प्रक्रिया और अपनी शुल्क संरचना भी तय करेंगे।

हमारे देश में जो कुछ निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनमें से कुछ तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन भारी तादाद में ऐसे विश्वविद्यालय केवल धन कमाने की मशीन के रूप में ही जाने जाते हैं। ऐसे निजी विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों को दिए गए अधिकांश विशेष अधिकारों का अंडर द टेबल खूब आनंद उठाते हैं। इस क्रम में जो सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थान आते हैं, जिन पर कि कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे संस्थान एक तो हमेशा संसाधनों की कमी से पीड़ित रहते हैं, वह विदेशी फैकेल्टी की नियुक्ति नहीं कर सकते। वित्त पोषित संस्थानों में होने वाली नियुक्तियां भी साफ–सुथरी नहीं होती हमेशा संदेह के घेरे में ही देखी जाती है (आप केस स्टडी के रूप में आजकल दिल्ली में चल रही नियुक्तियों को ट्रैक कर सकते हैं)। ऐसे संस्थानों में पाठ्यक्रम की संरचना पाठ्यक्रम सामग्री यूजीसी के दिशा निर्देशों द्वारा निर्धारित की गई है, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए सहायता लगातार कम होती जा रही है।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में परंपरागत रूप से शुल्क बहुत कम लिया जाता है। अब केंद्र सरकार राज्य के कोष पर निर्भरता कम करने की वकालत कर रही है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि फीस में बढ़ोतरी कर संसाधन जुटाना चाहिए। लेकिन सौ टके का सवाल है कि ऐसे में आर्थिक तंगी से गुजर रहे मेधावी छात्रों का क्या होगा? अमीर छात्र तो हर स्थिति में पढ़ लेंगे उन्हें अगर यहां के विश्वविद्यालयों में जगह नहीं मिलेगी तो अपने धन बल पर विदेशी विश्वविद्यालयों की शरण में चले जाएंगे लेकिन वह विद्यार्थी जिनके माता–पिता गरीब हैं उनके पास राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में जो तीन स्तरीय मॉडल आगे बढ़ रहा है जहां पहुंच भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित होगा न कि 'होने की जरूरत के आधार पर'। अधिकांश भारतीय लोकाचार और समाज की जरूरतों में निहित गुणवत्ता शिक्षा से वंचित रहेंगे। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल मानव संसाधन विकसित करने में पीछे होंगे। दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा परोपकार धार्मिक उद्देश्यों के लिए जितना व्यापक है उसका आधा भी नहीं बचेगा। आज की परिस्थितियों में एक औसत धनी भारतीय किसी वंचित बच्चे की शिक्षित करने और संस्थाओं को वित्त पोषित करने की वजाय मंदिरों में दान करना बेहतर समझता है। सब कुछ के बावजूद हमें समझना होगा कि हमारी सार्वजनिक विश्वविद्यालय प्रणाली हमारे राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्थित रूप से अपनाई गई है। इसमें एक उपयुक्त परिस्थितिकी तंत्र का विकास किया है। हमें इसकी कमियों को सुधार करने की जरूरत है, न कि किसी अन्य बाजार आधारित शिक्षा मॉडल को अपनाने की। ❑❑

अडानी प्रकरणः इतना हंगामा है क्यों बरपा?

आजकल अडानी उद्योग समूह की चर्चा है। उनकी कागजी अमीरी कम होने से कुछ लोग खुश तो कुछ नाराज है। संसद भी बंद रही और सर्वोच्च न्यायालय ने भी छोटे निवेशकों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखते हुए सेबी को अपनी नीति स्पष्ट करने और इस विषय में जांच करने को कहा है। वैसे, स्टॉक मार्केट की बढ़ोतरी या गिरावट कागजी होती है जबतक की शेयर की खरीदी या बिक्री न हो। वहाँ तो रोज कई लोग अमीर होते है तो कई गरीब। इसलिए शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की कितनी चर्चा होनी चाहिए यह सोचने की बात है। बाकी जमीनी हकीकत में किसी की माली हालत अच्छी है या नहीं यह देखने और समझने के और तरीके भी है और वह स्टॉक मार्केट से ज्यादा वास्तविक है। यह सही है की अडानी के बारे में हिंडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आयी है और उसमें कई बाते है। लेकिन उस रिपोर्ट की बातों में कितना दम है यह गुजरते समय के साथ सामने आयेगा, लेकिन इससे मोदी विरोधियों की मुद्दे ढूंढने की तिलमिलाहट जरूर सामने आयी है। इस रिपोर्ट का अडानी उद्योग समूह पर हकीकत में कोई असर हो न हो इस विषय की चर्चा से सामान्यों के मन में भारतीय उद्योगपतियों के बारे में शंका पैदा हुई है और वही चिंता का विषय हो सकता है।

क्या है यह हिंडेनबर्ग संस्था

हिंडेनबर्ग अनुसंधान करने वाली अमरीका की एक संस्था है जो 2017 से काम कर रही है। इस संस्था का कहना है की इसका अनुसंधान वित्तीय निवेश निर्णय लेने में सहायक होता है क्योंकि यह कंपनियों की आर्थिक अनियमितता, प्रबंधन की कमियाँ, जाहिर नहीं हुए लेन–देन व्यवहार, गैर कानूनी या अनैतिक तरीके से किया गया व्यापार या अपनाए गए वित्तीय आचरण तथा उत्पाद, वित्तीय तथा रेग्युलेटरी जानकारी नहीं देने के बारे में अनुसंधान करती है। इसके पहले यह संस्था, अमरीका या और अन्य देशों की कंपनियों के बारे में भी लिख चुकी है जैसे की आरडी लीगल हेज फंड, पेरशिंग गोल्ड, ओपको हैल्थ, पोलरिटी टीई, अफरिया, लिबर्टी हैल्थ सायन्स, यांगजा रिवर पोर्ट अँड लोजीस्टिक (चीन की कंपनी), एचएफ़ फूड्स, निकोला आदि आदि। इसमें बहुत सारी कंपनियाँ अमरीका की है। एक–दो चीन की और अब भारत की एक –अडानी उद्योग समूह–है। इस अनुसंधान संस्था का यह दावा भी रहता है कि बहुतायत मामलों में उनका कहना सिद्ध होता है। मतलब यह की यह संस्था विसलब्लोवर का काम करती है। कुछ कंपनियाँ ऐसे लिखे के खिलाफ अमरीका के कोर्ट में जा चुकी है। लेकिन ऐसे मान हानि दावों का आगे कुछ नहीं हो पाता, यह इतिहास है। भारत में भी राजनीति से प्रेरित बहुत लोग बहुत से लोगों के बारे में गलत–सलत बाते कहते है और उनके खिलाफ मान हानि के दावे भी होते है। बहुत हुआ तो माफी मांग कर समझौता हो जाता है। लेकिन बदनामी होने से जो तात्कालिक नुकसान होता है वह हो ही जाता है। यह केस भी ऐसा ही कहा जा सकता है।

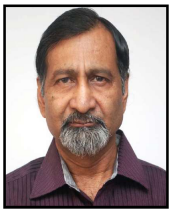

यह अच्छी बात है भारतीय रिजर्व बैंक इस पर नजर रखती है और बैंकों को जरूरी निर्देश देती है। ऐसे समय में बाहरी संस्था के ऐसे माहौल बिगाड़ने के उद्देश से लिखी रिपोर्ट को ज्यादा महत्व देना उचित नहीं होगा।

– अनिल जवलेकर

भारतीय संस्थाओं पर भरोसा जरूरी

हिंडेनबर्ग ने अडानी समूह के संबन्धित रिपोर्ट जनवरी 2023 में प्रकाशित की जिसमें अडानी उद्योग समूह, भारत सरकार और सेबी जैसी संस्थाओं के प्रति आरोप लगाए है। अडानी परिवार के सदस्यों को भी इसमें घसीटा गया है। इन आरोपों का आधार लोगों से बातचीत, कई डॉक्युमेंट्स की छानबीन वगैरह बताया गया है। यह सही है कि इसमें से बहुत

से आरोपों को देखने का नज़रिया अपना–अपना हो सकता है और अपने–अपने मतलब निकाले जा सकते है। लेकिन ऐसे विषयों पर भारतीय सेबी जैसे नियंत्रक और भारत की छानबीन करने वाली एजंसियों की बात मान लेना ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि वह जिम्मेवारी से ऐसी बातों की छानबीन करती रहती है। सरकार और उनकी एजंसियाँ भी अपने तरीके से तथ्य सामने रख सकती है विशेषतः अडानी समूह पर हुए भ्रष्टाचार और मनी लॉडरिंग के आरोपों के बारे में।

विरोधियों कि इतनी तिलमिलाहट क्यों

निश्चित ही जो लोग अडानी समूह की कंपनियों के किसी भी तरह से भागीदार है उनकी उलझन समझ में आ सकती है क्योंकि उनकी पूंजी इस उद्योगों में लगी है। सरकार के लिए भी यह रिपोर्ट शांति भंग करने वाली हो सकती है क्योंकि अभी–अभी भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना का धक्का वहन करके पटरी पर वापस लौट रही है और सरकार निजी पूंजी का साथ लेकर बहुत से विकास काम करना चाहती है। निश्चित ही शेयर मार्केट में हलचल होने से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी भी सकते में आ जाती है और घरेलू निवेश भी घबरा जाता है। प्लेज की हुई संपातियों की कीमत कम होना वित्तीय प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन विरोधी दल की तिलमिलाहट समझ में नहीं आती। उनके पास मोदी सरकार के विरोध में कोई मुद्दा नहीं है यह एक कारण हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकने वाले मुद्दे को लेकर इतनी तिलमिलाहट अच्छी नहीं कही जाएगी।

हंगामे से अर्थव्यवस्था को नुकसान

वैसे देखा जाए तो ऐसी रिपोर्ट हँगामा खड़ा करने के लिए ही होती है। आज भारत की अकेली ऐसी अर्थव्यवस्था है जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुक़ाबले अच्छा काम कर रही है। हाल ही में आयी रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट भी यहाँ की वित्तीय प्रणाली के स्थिरता की बात कर रही थी और कह रही है कि यहाँ के बैंक अच्छे स्थिति में है और अब कोई बैंक डूबने की स्थिति में नहीं है। ऐसे मौहोल में भारतीय स्थिरता और विकास पर शंका उपस्थित कर इसमें खलल डालने का काम ऐसी रिपोर्ट करती है, यह बात समझनी जरूरी है। और यह कोई नई बात नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी होना और यहाँ के स्थानीय उद्योगों का बढ़ना बाहरी ताकतों और पूंजी पतियों को अच्छा नहीं लगता है और वे उसको कमजोर करने में लगे रहते है। ऐसी रेपोर्टे वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है इसलिए भारतीय मीडिया या विरोधी दलो को हंगामे से बचना चाहिए।

सावधानता जरूरी

भारतीय उद्योग जगत में भी सब कुछ ठीक–ठाक है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। व्यापार उद्योग में फायदा कमाना मुख्य लक्ष्य होता है और उस फायदे के लिए कुछ भी करने को यह उद्योग तैयार रहते है। यह भी कोई छुपी बात नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहां के उद्योग नैतिक मूल्यों पर सदा काम करते है और सभी कायदे–कानून का पालन करते हुए उद्योग चलाकर लाभ कमाते है। लेकिन यह देखने के लिए और ऐसी गतिविधियां नियंत्रित करने के लिए भारत की अपनी व्यवस्था है और यहाँ एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है और उस पर भरोसा करके ही ऐसे प्रश्न सुलझाए जा सकते है। यह भी नकारा नहीं जा सकता की यहाँ की सरकारों का इतिहास वित्तीय संस्थाओं पर दबाव डालने का रहा है और उसके चलते बैंकों को पिछले पाँच वर्षों में डूबे कर्ज के रूप में 10 लाख करोड़ रुपए छोड़ने पड़े है। सामने आए बैंको के घोटाले भी यह बताते है कि बैंक अपने कर्ज देने में और सेक्यूरिटी लेने में गलती करती है और बैंकों को ऐसी गलत सेक्यूरिटी या उसकी आँकी गई गलत कीमत की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। यह अच्छी बात है भारतीय रिजर्व बैंक इस पर नजर रखती है और बैंकों को जरूरी निर्देश देती है। ऐसे समय में बाहरी संस्था के ऐसे माहौल बिगाड़ने के उद्देश से लिखी रिपोर्ट को ज्यादा महत्व देना उचित नहीं होगा।

यह जरूर है कि संबंधित भारतीय नियंत्रक और रिजर्व बैंक या ऐसे विषय में छानबीन करने वाली संस्थाओं ने रिपोर्ट में कही बातों को नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार ने भी अपनी तरफ से इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। विरोधी दलों को भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को समझकर बात करनी चाहिए और सरकार विरोध के लिए मुद्दे ढूंढने की तिलमिलाहट ऐसे रिपोर्ट द्वारा पूरी नहीं करनी चाहिए। ❑❑

ई–कॉमर्स में गेम चेंजर हो सकता है 'ओएनडीसी'

एक दशक से अधिक समय से, ई–कॉमर्स में भारत और दुनिया में भारी वृद्धि देखने को मिली है। भारत में कुल खुदरा व्यापार का लगभग 6.5 प्रतिशत आज ई–कॉमर्स के माध्यम से होता है। ई–कॉमर्स ने जीवन को बेहद आसान बना दिया है, क्योंकि लोगों को घर बैठे एक बटन क्लिक करने पर आसानी से वस्तुएं और सेवाएं मिल जाती हैं। रेल–बस टिकट हो या हवाई यात्रा, होटल बुकिंग हो या टैक्सी, ऑटो से आना–जाना सब कुछ बेहद सुविधाजनक हो गया है। इतना ही नहीं, ई–कॉमर्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की घरेलू और व्यावसायिक सेवाओं तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।

लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है, जिससे पारंपरिक व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है। सवाल केवल कमीशन का नहीं है, ये ई–कॉमर्स कंपनियां डेटा पर अपने एकाधिकार के कारण विभिन्न विक्रेताओं के बीच भेदभाव करती हैं और अपने पसंदीदा विक्रेताओं को वरीयता देती हैं और इस प्रकार अन्य विक्रेताओं को नुकसान होता है।

हालाँकि, ये कंपनियाँ अपने ग्राहकों को सस्ता सामान और सेवाएँ प्रदान करने का दावा करती हैं, लेकिन वास्तव में अपनी आर्थिक ताकत के चलते ये कंपनियां छोटे पारंपरिक दुकानदारों, ट्रैवल एजेंटों आदि को बाज़ार से बाहर करने के लिए उपभोक्ताओं को भारी छूट देती हैं। अपने स्वयं के पैसे से और ड्राइवरों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने भारी प्रोत्साहन भी दिया। लेकिन अब अपना व्यवसाय स्थापित करने के बाद, उबर सरीखे एग्रीगेट्रों के द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, और ड्राइवरों की कमाई का लगभग एक तिहाई इन एग्रीगेट्रों द्वारा छीन लिया जाता है।

ओएनडीसी को भी एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के शोषण को रोक सकती है, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को सुविधा प्रदान करके सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में भारी वृद्धि करने में भी सक्षम हो सकती है।

– स्वदेशी संवाद

एग्रीगेटर के रूप में काम करने वाली ई–कॉमर्स कंपनियां छोटे वेंडरों और गरीब कामगारों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हड़प रही हैं।ऐसे में उनके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो अपना शोषण होने दें या व्यवसाय छोड़ दें। इतना ही नहीं ई–कॉमर्स कंपनियों के कैश बर्निंग मॉडल की वजह से परंपरागत कारोबारी भी धंधे से बाहर हो रहे हैं। चाहे किराना दुकान हो या रेडीमेड परिधान की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान के शोरूम, या पारंपरिक ट्रैवल एजेंट, ई–कॉमर्स कंपनियों के आने से विभिन्न प्रकार के खुदरा व्यापार में लोगों के रोजगार का क्षरण हुआ है। कहा जा सकता है कि आज का ई–कॉमर्स समावेशी नहीं है।

हालाँकि, हम ई–कॉमर्स को बंद नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है; सवाल विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का है। क्या हम इन ई–कॉमर्स दिग्गजों के लालच पर रोक लगा सकते हैं? इन सवालों के जवाब भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में मिल रहे हैं, जो कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। ओएनडीसी नेटवर्क

ई–कॉमर्स को एक चैनल प्रदान कर रहा है। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक कड़ी प्रदान करने की कोशिश करता है, जो शोषणकारी नहीं है। इस प्रणाली में, ई–कॉमर्स कंपनियां डेटा पर एकाधिकार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से विक्रेताओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकती हैं। कुल मिलाकर ओएनडीसी एक ऐसा चैनल होगा जिसमें उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के विक्रेता, सेवा प्रदाता आदि को आसानी से खोज सकेंगे और ई–कॉमर्स बाजार में एकाधिकार के बजाय प्रतिस्पर्धा के आधार पर विक्रेताओं के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

ओएनडीसी क्या है?

ओएनडीसी सामान्य ई–कॉमर्स कंपनियों जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। आमतौर पर ई–कॉमर्स कंपनियां एक प्लेटफॉर्म के जरिए काम करती हैं। विक्रेता या सेवा प्रदाता संबंधित प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराते हैं और उन्हें कई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होता है। हालाँकि, ये प्लेटफ़ॉर्म उपभोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों को छूट और प्रोत्साहन का लालच देकर, अपनी आर्थिक ताक़त के बलबूते उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब उनका व्यवसाय स्थापित हो जाता है, तो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वे उपभोक्ता और विक्रेता, दोनों का शोषण करते हैं।

ओएनडीसी वास्तव में विभिन्न प्लेटफार्मों और उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी है जो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करता है। अभी तक सामान्य ई–कॉमर्स में विक्रेता और सेवा प्रदात्ताओं को प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होता था, इसलिए वे उन प्लेटफ़ार्मों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता प्लेटफॉर्म पर केवल उन्हीं विक्रेताओं को देख पाते हैं, जो उस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं।

ओएनडीसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों को ही पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन ओएनडीसी की शर्त यह है कि इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिन वेंडरों या सेवा प्रदाताओं ने खुद को पंजीकृत कराया है, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं ओएनडीसी पर आने वाले सभी ग्राहकों को दिखाई देंगी। यानी ओएनडीसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ भी अपारदर्शी नहीं है। यह प्रणाली जियोग्राफिक इंफरमेशन सिस्टम (जीआईएस) यानि भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से काम करती है और लाखों विक्रेताओं व करोड़ों उपभोक्ताओं को उनके स्थान यानि लोकेशन के आधार पर सुविधा प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपभोक्ता घर बैठे किसी रेस्तरां से खाना या किराना सामान मंगवाना चाहता है, तो ओएनडीसी प्रणाली में, आस–पास के सभी रेस्तरां या किराना स्टोर तक वो पहुँच सकता है और जो भी वो ख़रीदना चाहता है, ख़रीद सकता है। ये सभी विक्रेता और सेवा प्रदाता, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पंजीकृत होने के बावजूद, ओएनडीसी पर संभावित खरीदारों को दिखाई देंगे। हालांकि, जिन ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वेंडर पंजीकृत हैं, वे वेंडर के साथ अपने समझौते के अनुसार शुल्क लेना जारी रख सकते हैं, लेकिन व्यवसाय लाने के लिए प्लेटफ़ार्मों के बीच प्रतिस्पर्धा से उनका कमीशन अपने आप कम हो सकता है। हर प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने के लिए अपना कमीशन कम रखना चाहेगा।

इस प्रकार ओएनडीसी ई–कॉमर्स को प्लेटफार्मों के एकाधिकार से मुक्त करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ओएनडीसी ई–कॉमर्स बिजनेस के नियमों में बदलाव कर सकता है। हालांकि, ई–कॉमर्स कंपनियों ने भी ओएनडीसी के नेटवर्क में शामिल होने में रुचि दिखाई है और कुछ प्लेटफॉर्म और भुगतान कंपनियां भी ओएनडीसी के साथ पंजीकृत हो रही हैं। हालांकि ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवाओं ने अभी तक इस पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है, लेकिन कुछ नई ई–कॉमर्स मोबिलिटी कंपनियां ओएनडीसी में रुचि दिखा रही हैं।

ओएनडीसी को हाल ही में पेश किया गया है, ओएनडीसी प्रणाली में बहुत कम व्यवसाय किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि यह व्यवसाय निकट भविष्य में तेजी से बढ़ेगा। इससे छोटे ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भारी विज्ञापन खर्च के बिना उपभोक्ताओं तक पहुंचना संभव हो सकता है। बड़े या छोटे ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सभी पंजीकृत विक्रेता ओएनडीसी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को समान रूप से दिखाई देंगे, क्योंकि ओएनडीसी प्रोटोकॉल विभिन्न विक्रेताओं के बीच अंतर नहीं करता। यदि ओएनडीसी प्रणाली सफल होती है, तो इसके साथ–साथ ई–कॉमर्स के सभी फ़ायदे तो बदस्तूर मिलेंगे ही लेकिन इसकी अधिकांश कमियों से बचा जा सकेगा।

गौरतलब है कि अब तक मौजूदा सरकार के तकनीक समर्थित सभी प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। आज यूपीआई दुनिया में एक मिसाल बन चुका है और इसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जल्दी और बिना किसी लागत के संभव हो रहे है। आज दुनिया में जितने भी ऑनलाइन लेनदेन होते हैं उनमें से 40 फीसदी से ज्यादा भारत में हो रहे हैं। इसी तरह, ओएनडीसी को भी एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के शोषण को रोक सकती है, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को सुविधा प्रदान करके सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में भारी वृद्धि करने में भी सक्षम हो सकती है। ❑❑

हमें कृषि क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना चाहिए

महाराष्ट्र के किसानों का प्याज को लेकर प्रदर्शन अब लगता है फिर से राज्य सरकार के लिए आफत बनने जा रहा है। आखिर बार–बार ऐसा होता क्यों है। यह सब समझने के लिए मैं नासिक गया और वहां के किसानों से मिलने का और उनकी समस्याओं को जानने का मुझे हाल ही में मौका मिला। इस साल मौसम का बदलाव किसानों के अनुकूल नहीं रहा। नासिक के किसान इस बार इस बात को लेकर खुश थे कि फसलों पर कीड़ों का प्रकोप नहीं दिखा। तापमान बढ़ता है तो कीड़ों का असर कम रहता है।

इस तरह से गर्मी का ज्यादा असर प्याज की फसल पर तो नहीं था मगर नासिक में इन दिनों शाम का तापमान अचानक से कम हो रहा है। जब शाम का तपामान कम होता है तो नमी बढ़ जाती है जो कि प्याज की गांठों के लिए सही नहीं है। रबी की जब प्याज की पहली फसल आती है तो ज्यादा नमी की वजह से यह प्याज भंडारण के लिए अधिक उपयुक्त नहीं रहती। इसे ज्यादा दिन तक सहेज कर नहीं रखा जा सकता। खरीफ की फसल सर्दियों में होती है और ज्यादा नमी की वजह से उस प्याज का भंडारण संभव नहीं होता मगर रबी की फसल का भंडारण 5 से 6 महीने तक किया जा सकता है।

मगर रबी की अगेती फसल में ज्यादा नमी पाई जा रही है। इसलिए इस प्याज को 7–8 दिन से ज्यादा संरक्षित नहीं रखा जा सकता। ऐसे में व्यापारी इस प्याज को खरीदने से संकोच कर रहा है। दूसरी ओर पैदावार बढ़ गई है, इसलिए किसान को इसे निकालना ही है। किसान भी जानते हैं कि इस प्याज को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। महाराष्ट्र में प्याज के किसानों के संकट का एक कारण तो यह समझ में आया है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश के कुल प्याज उत्पादन का 40 फीसदी महाराष्ट्र में ही होता है।

नासिक में किसानों को जो दाम मिल रहा है वह 300 से 350 रुपए प्रति किंवटल का मिल रहा है। दूसरी ओर किसान को उसकी लागत प्रति किलोग्राम 10 से 12 रुपए आती

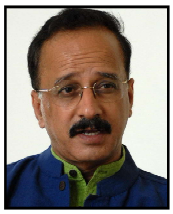

हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे अर्थशास्त्री कभी खेत में जाते ही नहीं हैं, कभी गांव में रहते ही नहीं हैं इसलिए वे इसका महत्व नहीं जान पाए। हमें कृषि क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना चाहिए।

– देविन्दर शर्मा

है। इसलिए किसानों का गुस्सा हम सबके सामने है। यही वजह है कि प्याज के किसान नासिक से मुम्बई के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। किसान पांच साल बाद फिर से पैदल मार्च पर हैं। महामारी काल में हमने देखा कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे आई तो उस समय कृषि क्षेत्र ने ही सबसे अच्छा साथ दिया।

पिछली तिमाही में भी कृषि विकास दर सबसे अच्छी थी। पता नहीं क्यों हमारे नीति निर्धारकों को यह समझ नहीं आता कि कृषि क्षेत्र पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत हमारी सोच है, जो संभवतः कृषि समर्थक नहीं है। हम उद्योग के लिए कृषि क्षेत्र का बलिदान देना चाहते हैं। नीति निर्धारकों का मानना है कि जब तक हम लोगों को गांवों से निकालकर शहरों में नहीं ले आते तब तक आर्थिक विकास का रास्ता सुदृढ़ नहीं होगा।

यह कोई मौलिक सोच नहीं है बल्कि देखा जाए तो यह पश्चिम की नीतियों का कट–कॉपी–पेस्ट है। यानी नकल है। इस नकल को ही आर्थिक सुधार कहा जा रहा है। यही वजह है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। हमारे पास दो आर्थिक पैमाने होते हैं– एक, सकल उत्पादन (जी.बी.ओ.), इसमें हम कृषि के कुल उत्पादन को नाप लेते हैं। यह 50 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन है। इसके अलावा दूसरा सकल मूल्य अतिरेक होता है।

इसका अर्थ है कि आप अपनी लागत को निकाल दें तो जो बाकी लाभ है उसे सकल मूल्य अतिरेक (जीबीए) कहते हैं। यह जी.बी.ए. लगभग 40 लाख करोड़ रुपए है। इस तरह कृषि क्षेत्र का जी.बी.ओ. और जी.बी.ए. का जो अनुपात है 80 फीसदी से अधिक

पिछली तिमाही में भी कृषि विकास दर सबसे अच्छी थी। पता नहीं क्यों हमारे नीति निर्धारकों को यह समझ नहीं आता कि कृषि क्षेत्र पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत हमारी सोच है, जो संभवतः कृषि समर्थक नहीं है।

है। यह भारत के अन्य सभी आर्थिक सैक्टरों चाहे वह वित्त है, सेवाएं हैं, भारी उद्योग है, में सबसे ज्यादा बेहतर कृषि क्षेत्र का है। इस तरह उत्पादकता के लिहाज से सबसे कुशल क्षेत्र कृषि क्षेत्र है।

दूसरी ओर कृषि से जो आय है वह इसलिए सबसे कम है, क्योंकि वह जितनी मिलनी चाहिए उतनी किसानों को नहीं दी जा रही। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने से सरकार ने हमेशा इंकार किया है। सबसे कुशल क्षेत्र होने के बावजूद वहां किसान की आय नहीं बढ़ी है तो इसके कारण अब स्पष्ट होने चाहिएं। मीडिया में भी यह गलत छवि बनाई जा रही है कि कृषि देश पर बोझ है। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर इसे आगे बढ़ाया जाता है तो इसमें हमारी आर्थिक समस्याओं के समाधान भी छुपे हैं। अब तो अर्थशास्त्री भी इस बात को मान रहे हैं कि देश में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। इसके बावजूद हमारे नीति निर्धारक उसी पुरानी सोच से काम कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन लाजवाब है। यूक्रेन जंग से दुनिया के सामने जो अनाज संकट उत्पन्न हो गया था उससे बचाने में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई। इसके अलावा कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो वह भी किसानों की मेहनत का ही नतीजा है। कोरोना काल में माना जा रहा है कि शहरों से करीब 10 करोड़ लोगों का पलायन हुआ। इनमें से काफी लोग वापस शहर नहीं आए। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे अर्थशास्त्री कभी खेत में जाते ही नहीं हैं, कभी गांव में रहते ही नहीं हैं इसलिए वे इसका महत्व नहीं जान पाए। हमें कृषि क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना चाहिए। ❑❑

https://www.punjabkesari.in/blogs/news/we-must-rebuild-the-agriculture-sector-1789394

बढ़ते ही जा रहे है खेती पर खतरे

असामान्य मौसमी घटनाओं ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि आजीविका और जीवन के लिए संकट उठ खड़ा हुआ है। पिछले दिनों ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने कई राज्यों के किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कई लोगों को यह अच्छी लग सकती है, कई लोग महसूस करते हैं कि इससे उन्हें उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन हजारों किसानों के लिए यह स्थिति मुसीबत का कारण बन गई। मार्च और अप्रैल के महीने में बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हुई। तैयार हो चुकी गेहूं और सरसों की फसल बारिश की चपेट में आ गई। पहले आंधी ने फसलों को नीचे गिराया और फिर बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। नुकसान इस कदर हुआ कि किसानों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई।

मौसम के इस बदलाव को पर्यावरणविदों के साथ–साथ कृषि विज्ञानी भी जलवायु संकट से जोड़कर देख रहे हैं। कृषि विज्ञानियों का मानना है कि खेती पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को गंभीरता से नहीं लिया गया तो निकट भविष्य में भारी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मौसम अब इसी तरह बदलता रहेगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट भी कहती है कि आगामी 15 वर्षों में जलवायु संकट के कारण पैदावार में कमी की वजह से भारत के 4:30 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाएंगे। अगले डेढ़ दशक में देश की धरती के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि तय मानी जा रही है। परिणाम स्वरूप मानसून की तीव्रता में 10 फीसद तेजी आएगी, यानी कम समय में बहुत अधिक बारिश, पानी की बूंदों का आकार बड़ा होने, बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने की आवृत्ति लगातार बढ़ेगी।

जलवायु संकट के कुप्रभाव को वापस कर पाना तो संभव नहीं है लेकिन उपाय के तौर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदावार के बचाव की कार्य योजना तैयार की जा सकती है। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य

यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल के खतरों से भी देश को बचाना होगा। इससे बढ़ती जलवायु संकट की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी और खेती किसानी को भी बचाया जा सकेगा।

– शिवनन्दन लाल

प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आसमानी बिजली गिरने की घटनाओं में 15 से 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। कम समय में अत्यधिक बारिश से बाढ़ के हालात पैदा होंगे, बारिश के बाद अन्य स्थानों पर लंबे सूखे के भी हालात बन रहे हैं। अनुमान के मुताबिक तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि से देश का गेहूं उत्पादन एक करोड़ टन से कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से फसलों में प्रोटीन सहित अन्य तत्वों की मात्रा भी कम होती जा रही है। पशुओं की प्रजनन क्षमता में कमी के साथ उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी गिरावट आ रही है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान के मुताबिक जलवायु संकट से वर्ष 2050 तक चावल के उत्पादन में एक प्रतिशत और मक्का तथा कपास के उत्पादन में क्रमश 13 और 14 प्रतिशत कमी आने की आशंका जताई गई है। पिछले साल फसल पकते समय अचानक गर्म हवाएं चलने से गेहूं उत्पादन के पूर्वानुमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई थी। खरीफ की फसलों में उड़द, मूंग, तिलहन और धान का उत्पादन 2023 में अनुमान से कम हो रहा है। इसकी वजह मानसून में देरी और अचानक आंधी तूफान बारिश हो ओला की अधिकता को माना जा रहा है।

देश में कृषि में जीवांश की मात्रा तेजी से कम हो रही है। कृषि योग्य मिट्टी में आवश्यक जैविक तत्व की मात्रा में 3 से 6 प्रतिशत तक की गिरावट मापी गई है।

वैश्विक जलवायु सूचकांक में जिन देशों पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, उनमें भारत 14वें स्थान पर है। भारत में 2050 तक औसत वर्षा के दिनों में 60 प्रतिशत की गिरावट अनुमानित है। भारत के पड़ोसी देशों में उत्पादन की गिरावट से विकराल स्थितियां खड़ी हो सकती हैं, जिसका असर भारत

जलवायु संकट की चुनौती के मद्देनजर कम लागत और कम सिंचाई वाले, मौसमी परिवर्तन सहन करने वाले बीज विकसित करने की जरूरत होगी। फसलों की मौसमी परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए अब देश को हाइड्रोजेल तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। विकसित देशों में लोकप्रिय हाइड्रोजेल बीज अंकुरण जल की वृद्धि सहित फसली पौधों के सूखे और गलन से बचाने का कार्य करते हैं।

पर भी पड़ेगा। किसानों को छिटपुट छोटे और क्षणिक लाभ देने के अलावा भारत सरकार ने अभी तक इस इन संकटों से कृषि को बचाने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना पेश नहीं की है।

ऐसे में कम समय में अधिक वर्षा के अंदेशे के मद्देनजर वर्षा जल को न केवल खेतों में रोकना बल्कि से जमीन के अंदर भी पहुंचाना है। प्रत्येक खेत में तालाब तैयार करना, मेड़ बांधना और उन पर पेड़ लगाना अनिवार्य करना होगा। तेज गर्मी और कम समय में वर्षा की सिंचाई के लिए अब एकमात्र विकल्प वर्षा जल के संचयन से खेती करना ही है। ऐसे में भूमिगत जल सुरक्षित बनाने एवं वर्षा जल को नलकूपों के माध्यम से भूमि में उतारने की प्रक्रिया अपनानी होगी। भारत भूमिगत जल दोहन के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है इसके विपरीत भूमिगत जल संचय में देश का योगदान नगण्य है। जैविक कृषि से संबंधित एक अनुसंधान बताता है कि अगर कृषि भूमि की कार्बनिक क्षमता में एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो प्रति हेक्टेयर जमीन की जलधारा में 75000 लीटर की वृद्धि संभव है। भीषण गर्मी में खेतों में संरक्षित जल को वाष्पीकरण से बचाने के लिए खेतों, तालाबों के ऊपरी सतह पर सोलर पैनल लगाकर पानी के वाष्पीकरण को रोकने के साथ खेतों में बिजली उत्पादन की योजना को मूर्त रूप दिया जाना चाहिए।

देश के कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अधिक पैदावार वाले बीज विकसित कर रहे हैं जिनको अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। जलवायु संकट की चुनौती के मद्देनजर कम लागत और कम सिंचाई वाले, मौसमी परिवर्तन सहन करने वाले बीज विकसित करने की जरूरत होगी। फसलों की मौसमी परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए अब देश को हाइड्रोजेल तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। विकसित देशों में लोकप्रिय हाइड्रोजेल बीज अंकुरण जल की वृद्धि सहित फसली पौधों के सूखे और गलन से बचाने का कार्य करते हैं। पानी के वाष्पीकरण को कम करने के साथ हाइड्रोजेल 40 डिग्री सेल्सियस क्योंकि तापमान तक कार्य करने में सक्षम होते हैं अपने सूखे वजन से 400 गुना पानी सुरक्षित कर सूखे के दौरान फसल की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।

देश में नाइट्रोजन का अत्यधिक उत्सर्जन भी जलवायु संकट का एक बड़ा कारण है। नाइट्रोजन का सीमित उपयोग पौधों को अचानक पोषक तत्व देने और पौधों के निर्माण में आवश्यक है, लेकिन इसका अधिक इस्तेमाल मृदा की जल अवशोषण क्षमता और जैव विविधता के लिए अत्यधिक नुकसान देह है। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल के खतरों से भी देश को बचाना होगा। इससे बढ़ती जलवायु संकट की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी और खेती किसानी को भी बचाया जा सकेगा। ❑❑

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी जी का 'स्वदेशी चिंतन'

स्वदेशी जागरण अभियान के महानायक एवं राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी जी के समग्र व्यक्तितव को समझना कोई सरल और सहज कार्य नहीं है। इसके लिए चाहिए स्वदेशी मंत्र, स्वदेशी यंत्र से अनुप्राणित किसी कर्मयोगी का साधना अभियान। श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगडी (दत्तात्रेय बापूराव ठेंगड़ी) का जन्म 10 नवम्बर, 1920 को आर्वी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता श्री बापूराव दाजीबा ठेंगड़ी, जो सुप्रसिद्ध अधिवक्ता थे तथा माता श्रीमती जानकी बाई ठेंगडी, जो आध्यात्मिक अभिरूची से सम्पन्न, भगवान दतात्रेय की परम भक्त थी। परिवार में एक छोटा भाई श्री नारायण ठेंगड़ी और एक छोटी बहन श्रीमती अनुसूया थी।

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की शिक्षा का सफ़र एल.एल.बी. तक रहा। उन्होंने यह उपाधि मॉरिश कॉलेज, नागपुर से वर्ष 1941 में प्राप्त की थी। तत्पश्चात वर्ष 1942 से (14 अक्टूबर 2004) देहावसान तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में देश को अपनी सेवायें दी। ठेंगड़ी जी बाल्यकाल से ही संघ शाखा में जाया करते थे। ठेंगडी जी हिदी, बंगाली, संस्कृत, मलयालम, अंग्रेजी तथा मराठी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। ठेंगड़ी जी में नेतृत्व की अपार क्षमता थी। वह अपने प्रारंभिक काल में ही वानर सेना आर्वी तालुका कमेटी के 1935 में अध्यक्ष रहे। 1935–36 में मुंसिपल हाईस्कूल 'आर्वी विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष रहे। 1935–36 में ही मुंसिपल हाई स्कूल 'गरीब छात्र फंड' समिति के सचिव रहे। 1936 में 'आर्वी गोवारी झुग्गी झोपड़ी मंडल' के संगठक रहे। 1936–1938 में 'हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन सेना', नागपुर के प्रोबेशनर रहे।

'स्वदेशी' केवल भारत के आर्थिक संकट और विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद की गुलामी का उत्तर नहीं, ढह गई साम्यवादी और ढहती जा रही पूंजीवादी व्यवस्था के पश्चात समस्त संसार के लिए एक 'तीसरा विकल्प' है।

– डॉ. युवराज सिंह

ठेंगड़ी जी अपने जीवन काल में संघ के संघ प्रेरित संस्थाओं में कार्यरत रहे। संघ के स्वाभाविक विकास क्रम में विभिन्न संस्थाओं का तथा रचनाओं का गठन और संचालन करने में ठेगडी जी की अहम् भूमिका रही है। ठेंगड़ी जी जिनके संस्थापक रहे उनमें – अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (9 जुलाई, 1949), भारतीय मजदूर संघ (23 जुलाई, 1955 – भोपाल), भारतीय किसान संघ (4 मार्च, 1971 – कोटा), स्वदेशी जागरण मंच (22 नवंबर, 1991 – नागपुर), सामाजिक समरसता मंच (14 अप्रैल, 1983), सर्वपंथ समादर मंच (14 अप्रैल, 1991 – मुंबई) प्रमुख रहे। इसके साथ ही 'अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद' (9 जुलाई, 1949) एवं 'भारतीय विचार केन्द्रम' (7 अक्तूबर, 1982 – थिरुवानन्तपुरम) के मार्गदर्शक रहे। ठेंगडी जी का सभी संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार सिद्धांत अधिष्ठान देने में योगदान प्राथमिक रहा है। इनके अलावा अनेकों फेडरेशन, एसोसिएशन, परिषदें,

फोरम, यूनियन, मंडल, समाज के संरक्षक, सदस्य एवं प्रतिष्ठापना प्रमुख रहे। ठेंगडी जी 1964 से 1976 तक राज्यसभा सदस्य रहे और इन्होने 'भारतीय जनता पार्टी' के गठन में विशेष भूमिका भी निभाई।

ठेंगड़ी जी की लेखन में भी विशेष रूचि थी, जिससे अपने विचारों को आम कार्यकर्त्ता एवं भारतीय नागरिकों तक पहुंचा पायें। ठेंगडी जी ने हिंदी, अंग्रेजी एवं मराठी भाषा में अनेकों पुस्तकें, लेख, भाषण एवं प्रस्तावना लिखी। हिंदी भाषा में उन्होंने 'एकात्म मानव दर्शन', 'कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर', 'प्रचार तंत्र', 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार', 'शिक्षा में भारतीयता का परिचय', 'हमारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर', 'जागृत किसान', 'राष्ट्र–चिंतन', 'हिंदू मार्ग' (थर्ड वे का अनुवाद), 'राष्ट्रीय श्रम दिवस', 'कार्यकर्त्ता', 'राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण' इत्यादि पुस्तकें लिखी। अंग्रेजी भाषा में 'प्रोसपेक्टिव', 'मॉर्डनिजेशन विदआउट वेस्टर्नाइजेशन', 'कंज्यूमर विदआउट सॉवरजेन्टी' 'थर्ड वे', फोकस ऑन सोशियल इकोनोमिक प्रोब्लमस', 'कम्प्यूटराईजेशन', 'वाई भारतीय मजदूर संघ' और मराठी भाषा में 'चिंतन पाथेय', 'वक्तृत्वाची पुर्वतयारी' एवं 'एरणीवरचे घाव' पुस्तकों के लेखक रहे है। ठेंगडी जी ने अन्य प्रमुख पुस्तकों में प्रस्तावना भी लिखी जिनमे 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन', 'स्वदेशी व्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन', 'हिन्दू इकोनॉमिक्स', 'राजकीय नेतृत्व', 'श्रम समन्वय विचार', 'कल्पवृक्ष' इत्यादि शामिल रही है।

इसके अलावा देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर साउथ अफ्रीका के डरबन में थर्ड वे विश्व हिंदू सम्मेलन में अपना विषय रखा। 6–8 अगस्त, 1993 को विश्व शांति के लिए वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर में वाशिंगटन डी. सी. में ठेंगडी जी ने अपना भाषण दिया।

टूटती पूंजीवादी व्यवस्था और समाप्त हो गए कम्युनिज्म के बाद निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व को किसी आर्थिक विकल्प की आवश्यकता पड़ेगी। कौन देगा यह विकल्प? इसी को स्वदेशी के रूप में ठेकड़ी जी ने प्रस्तुत किया। 'स्वदेशी' केवल भारत के आर्थिक संकट और विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद की गुलामी का उत्तर नहीं, ढह गई साम्यवादी और ढहती जा रही पूंजीवादी व्यवस्था के पश्चात समस्त संसार के लिए एक 'तीसरा विकल्प' है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो धर्म है और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वधर्म है, भौतिक और आर्थिक स्तर पर वही स्वदेशी है। स्वधर्म, स्वदेश, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वशासन एक दूसरे से संबंध और समव्याप्त है। इनमें से किसी एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह अमेरिका के आर्थिक साम्राज्यवाद और विकासशील देशों के आर्थिक शोषण को एक सफल और सार्थक चुनौती है।

श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का व्यापार, निवेश सम्बन्धी उपक्रमों का व्यापार तथा कृषि समझौता, डंकेल प्रस्तावों का व्यापक अध्ययन करने के पश्चात् विकसित देशों के साम्राज्यवादी षडयंत्रों से राष्ट्र को सावधान किया और कहा कि ''विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, पश्चिमी देशों के शोषण के नये हथियार है, जिनके माध्यम से साम–दाम–दंड–भेद का उपयोग करते हुए विकासशील तथा अविकसित देशों का शौषण करना चाहते है।'' दत्तोपंत जी ने ''डंकेल प्रस्ताव को गुलामी का दस्तावेज माना'' और इस आर्थिक साम्राज्यवादी अर्थात् आर्थिक गुलामी के खिलाफ व्यापक जन–आन्दोलन खड़ा किया।

इस आंदोलन को ठेंगडी ने स्वतंत्रता का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कहा और इस संग्राम को चलाने के लिए 22 नवम्बर 1991 को नागपुर में 'स्वदेशी जागरण मंच' की स्थापना की। स्वदेशी आन्दोलन, कम समय में ही राष्ट्रव्यापी आन्दोलन बन गया। वास्तव में स्वदेशी आन्दोलन के माध्यम से श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने वैश्विक आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया। स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी साम्राज्यवाद को जबरदस्त चुनौती दी। इसका परिणाम कोरोना काल में बखूबी देखा जा सकता है, बिना वैश्विक सहायता के भारत स्वाभिमान के साथ अपने सम्मान को बचाया भी और इस आपदा को अवसर में बदलकर विश्व के समक्ष एक उदहारण भी बना।

वास्तव में अब 'स्वदेशी' भारत में लड़ा जाने वाला एक 'धर्मयुद्ध' है, जो स्वात्म की अभिव्यक्ति का अनुष्ठान है। 'स्वदेशी' भारत का रक्षा कवच है और उसका विरोध भारत पर आक्रमण है। अब यह निर्णय करने का समय है कि आप किसके पक्ष में खड़े है – अपने राष्ट्रधर्म की रक्षा के साथ या उस पर आक्रमण करने वालों के साथ। क्योंकि स्वदेशी किसी देश का केवल अर्थतंत्र ही नहीं, अध्यात्म भी है। केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, जीवन का दृष्टिकोण और स्वराष्ट्र की पहचान भी स्वदेशी है। स्वदेशी देश की प्राणवायु है। स्वराज और स्वाधीनता की गारंटी है। स्वदेशी के अभाव में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानसिक स्वतंत्रता सर्वथा असंभव है। ❑❑

संदर्भ

1. ठेंगड़ी द. बा. (2011), 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता अधिष्ठानः व्यक्तिमत्त्वः व्यवहार', भारतीय विचार साधना पुणे प्रकाशन, पुणे।
2. ठेंगड़ी, दत्तोपंत, (1997), 'नई चुनौतियाँ', सुरुचि प्रकाशन, दिल्ली।
3. शुक्ल, भानुप्रताप, (संपा. देवेश चन्द्र), (1998) 'स्वदेशी चेतना', अभिरुचि प्रकाशन, दिल्ली।
4. डोगरा, अमर नाथ (संपा.) (2015), 'दत्तोपंत ठेंगडी जीवन दर्शन', (खण्ड–1), सुरुचि प्रकाशन, दिल्ली।
5. ठेंगड़ी, दत्तोपंत, (1997), 'भारतीयता और समाजवाद', रामनरेश सिंह प्रकाशक, कानपूर।
6. ठेंगड़ी, दत्तोपंत, (1997), 'डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा', लोकहित प्रकाशन, लखनऊ।
7. ठेंगड़ी, दत्तोपंत एवम शेषाद्री हो. वे., (1991), 'बाबा साहब अम्बेडकर', लोकहित प्रकाशन, लखनऊ।

मातृभाषाः सांस्कृतिक पहचान की आधारशिला

21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हमें मातृभाषाओं के महत्व को समझने और अपने जीवन में अपनाने का दिन है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता एवं सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, तथा मातृभाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देश में प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में ही प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

मातृभाषा, जिसे पहली भाषा या मूल भाषा के रूप में भी जाना जाता है, किसी भी व्यक्ति की पहचान, बौद्धिक विकास, संचार कौशल और उसकी संस्कृति और विरासत से भावनात्मक जुड़ाव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक व्यक्ति की मातृभाषा उसकी सांस्कृतिक पहचान और विरासत से जुड़ी होती है, और उसे उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विगत 50 वर्षो में हुए 150 से अधिक अध्ययनो व अनेको प्रयोगों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ है कि जिन बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, वे अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास मजबूत होता है।

इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति की मातृभाषा आमतौर पर वह भाषा होती है जिसमें वे सबसे अधिक धाराप्रवाह होते हैं, जिससे वे खुद को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं और सहज और परिचित तरीके से दूसरों के साथ संवाद कर सकते हैं। मातृभाषा भावनात्मक महत्व रखती है और व्यक्तिगत यादों और अनुभवों से जुड़ी होती है, जिससे यह व्यक्ति की भावनात्मक भलाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। मातृभाषाओं की विविधता को संरक्षित करना और उसका जश्न मनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारी दुनिया को समृद्ध करती हैं और विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और दृष्टिकोणों से भी परिचित कराती है।

इसीलिए भारत की शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को मान्यता देती है। नीति में कहा गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। यह देश में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर देती है। एनईपी 2020 में एक तीन–भाषा फॉर्मूला भी प्रस्तावित है, जहां छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ–साथ हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जा सके और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया जा सके। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य स्कूलों में भाषा–समृद्ध वातावरण बनाना भी है, जहाँ छात्रों को विभिन्न भाषाओं

मातृभाषा के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों दोनों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मातृभाषा को संरक्षित करने का एक तरीका दैनिक जीवन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना और भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना है।

– डॉ. जया शर्मा

और संस्कृतियों से अवगत कराया जाए, तथा विभिन्न भाषाओं को सीखने और उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एनईपी 2020 विभिन्न भारतीय भाषाओं में शिक्षण और सीखने की सामग्री विकसित करने के साथ–साथ भाषा शिक्षा और शिक्षाशास्त्र में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर देती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षण उच्च गुणवत्ता वाला बने और उनके उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा मिले।

हमारी सांस्कृतिक विरासत और भाषाई विविधता का अहम हिस्सा होते हुए भी मातृभाषाएं दुर्भाग्यवश, उपयोग एवं मान्यता की कमी के कारण विलुप्त हो रही है, और मातृभाषा को आज की दुनिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मातृभाषाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और मंदारिन जैसी प्रमुख भाषाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान का नुकसान हो रहा है। हाल ही में विलुप्त हुई भाषाओं के कुछ उदाहरणों में जापान में ऐनू, उत्तरी अमेरिका में युची और इंडोनेशिया में ल्होकोमावे शामिल हैं। यूनेस्को के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि अगली सदी में दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत भाषाओं के लुप्त होने का खतरा है।

संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, इसे कई भाषा की जननी माना जाता है, क्योंकि विश्व की कई दूसरी भाषाओं में संस्कृत के शब्दकोशो से लिए गए कई शब्द हैं, जैसे अनानास, ज्यामिति, इत्यादि। संस्कृत की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। संस्कृत का उपयोग विद्वता, धार्मिक प्रवचन और कलात्मक अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में किया जाता रहा है, और इसने दर्शन, साहित्य, विज्ञान और आध्यात्मिकता जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। संस्कृत अपनी व्याकरण और समृद्ध शब्दावली के लिए जानी जाती है, और इसे दुनिया की सबसे व्यवस्थित और परिष्कृत भाषाओं में से एक माना जाता है। इसके बावजूद, हाल की शताब्दियों में संस्कृत के उपयोग में कमी आई है।

संस्कृत भाषा के विलुप्त होने से ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि संस्कृत विलुप्त हो जाती है, तो इस सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान का बहुत कुछ खो जाएगा। संस्कृत की समृद्ध साहित्यिक परंपरा, जिसमें महाकाव्य कविताएं, ज्योतिष ग्रंथ, वैज्ञानिक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं, नई पीढ़ियों के लिए सुलभ नहीं हो पायेगी, और इन ग्रंथों में निहित अद्वितीय दार्शनिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि खो जाएगी। इसके अलावा, संस्कृत के विलुप्त होने का भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। संस्कृत भारत–यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और इसने हिंदी, जर्मन एवम कई यूरोपीय भाषाओं को प्रभावित किया है।

शिक्षा और समाज के अन्य क्षेत्रों में प्रमुख भाषाओं के प्रति पूर्वाग्रह भी है, जिसके कारण लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करने के अवसरों की कमी और सांस्कृतिक विरासत और भाषाई विविधता के लिए मान्यता की कमी है जो इन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है। डिजिटल तकनीक का उदय भी एक कारण है, मातृभाषाओं के उपयोग में गिरावट आने का। शिक्षा में एक ही अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को मध्यम बना लेने से विश्व में अनेक क्षेत्र भाषाये विलोपित हो रही है। "ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष न्युनतम 10 भाषाएं लुप्त हो रही है और आज विश्व में जो 6000 भाषाएं बोली जा रही हैं उनमें से आधी अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। ये भी अनुमान है कि मानव सभ्यता के इतिहास में 30,000 भाषाये विलुप्त हो चुकी है। केवल संस्कृत, हिब्रू, ग्रीक, मंदारिन ही ऐसी प्राचीन भाषाएं हैं जो 2000 वर्ष तक जीवित रही है। अंग्रेजी आज विश्व के केवल 17 प्रतिशत लोगो द्वारा बोली जाती है, तब भी 68 प्रतिषत वेब पेज अंग्रेजी में है।

मातृभाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उनके उपयोग और संरक्षण का समर्थन करने वाली नीतियों और पहलों को बढ़ावा देना समय की मांग बन गया है।

मातृभाषा के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों दोनों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मातृभाषा को संरक्षित करने का एक तरीका दैनिक जीवन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना और भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना है। भावी पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण के लिए लिखित रूप में भाषा का प्रलेखन भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे सांस्कृतिक आयोजनों, रीति–रिवाजों और परंपराओं में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। सरकारें आधिकारिक मान्यता प्रदान करके और मातृभाषा के विकास में सहायता करके भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मातृभाषा सहित कई भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने से बहुभाषावाद और भाषाई विविधता को बढ़ावा मिल सकता है। भाषा समुदायों के साथ सहयोग लुप्तप्राय सहित उनकी भाषा की रक्षा और प्रचार करने के लिए आवश्यक है। अंत में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भाषा के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करके मातृभाषा के अंतर–पीढ़ी संचरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ❑❑

कहां गुम हो रही छोटी नदियां

भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास के लिए नदियां अजस्र स्रोत के रूप में आदिकाल से कार्य करती रही हैं। भारतीय नदियों में सिंधु ,गंगा ,यमुना ,ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, राप्ती, कृष्णा एवं कावेरी आदि नदियों के तट पर अनेक नगर अस्तित्व में आए तथा विकसित होकर महानगर के रूप में परिणत हो गए, किंतु इन बडी नदियों को जीवन देने वाली अनेकानेक छोटी नदियां जो अपने साथ जल धन की अपार राशि को लाकर इन नदियों में समर्पित करती रही, ऐसी छोटी नदियां अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। जहां एक ओर भूगर्भ के जल का असीमित दोहन छोटी नदियों के जीवन को छीनने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास के परिणामस्वरूप इन छोटी नदियों पर बांध बनाकर तथा बचे हुए जल में जगह जगह चेक डैम बनाकर इनका जीवन छीना जा रहा है।

यहां पर इस तथ्य की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार शरीर का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर से रक्त को एकत्र कर धमनियों को प्रेषित कर जीवन को संचालित करता है, उसी प्रकार से इन छोटी नदियों द्वारा जल की अपार राशि का संग्रहण कर तथाकथित बड़ी नदियों को प्रेषित किया जाता है, जिसके बल पर ही तथाकथित बड़ी नदियां विशाल स्वरूप को ग्रहण करती हैं, किंतु छोटी नदियों के समक्ष ही अस्तित्व का संकट उपस्थित हो जाने के कारण विशाल नदियों को भी अपार जल की राशि न मिल पाने से उनके अस्तित्व के समक्ष भी संकट उपस्थित होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ऐसी प्रमुख नदियों में हिंडन तथा काली नदी प्रमुख हैं। इसी तरह प्रयागराज की ससुर खदेरी नदी तथा मनसयिता एवं चित्रकूट की मंदाकिनी, गुंता नदी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। मंदाकिनी नदी चित्रकूट स्थित पर्वतमाला के सती अनुसूया आश्रम से निकलकर जिले के अनेकानेक गांवों की भूमि को सिंचित करती हुई, वहां के जीव–जंतुओं को अपने रस से जीवन प्रदान करती हुई महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थल राजापुर में यमुना नदी से मिलती है। यमुना नदी में मिलने से पूर्व मंदाकिनी में अनेक क्षेत्रीय छोटी–छोटी नदियां मिलकर उनके जल प्रवाह को अपने–अपने जल से आपूरित कर गति प्रदान करती हैं।

शासन व्यवस्था बड़ी नदियों के साथ ही छोटी नदियों के संरक्षण संवर्धन एवं उनके प्रदूषण मुक्त होने को सुनिश्चित करने का दायित्व स्वयं निभाये, तभी यह नदियां बचेगी तथा धरती में जल होगा और उससे जीवन भी सुरक्षित बना रहेगा

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

अनुसूया आश्रम से निकलकर चित्रकूट में ही आने पर मां मंदाकिनी से पयश्विनी नदी कामदगिरि पर्वत के पास स्थित ब्रह्म कुंड से निकलकर चित्रकूट में रामघाट में मिलती थी, इसी प्रकार कामदगिरि पर्वत से निकल कर सरयू नदी पयश्विनी नदी के साथ मां मंदाकिनी से रामघाट पर मिलती थी और यहीं पर सरयू ,पयश्विनी एवं मंदाकिनी का संगम होता था, किंतु अब सरयू एवं पयश्विनी लुप्त हो गई हैं।

यह अलग बात है कि चित्रकूट में पयस्विनी के महत्व को देखते हुए अब लोग मंदाकिनी को ही पयश्विनी कहने लगे हैं। इस तथ्य से बहुत ही कम लोग परिचित हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन तपोधाम चित्रकूट में कभी पयस्विनी और सरयू नदियां भी बहती थी। जहां तक गुन्ता नदी का प्रश्न है राजस्व रिकार्ड में उसे नदी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया किंतु वह मूल रूप से वर्ष पर्यंत बहने वाली सदानीरा छोटी नदी थी,जिसके जल से समीपवर्ती जीव जंतुओं को जीवन रस प्राप्त होता था तथा समीपवर्ती भूमि सिंचित होकर सोना उगलती थी। कालांतर में वर्ष 1974 में गुन्ता नदी पर बांध बनाकर उसे कैद कर दिया गया और वह अपने अस्तित्व को गंवा बैठी। गुन्ता नदी चित्रकूट के ही ग्राम रैपुरा के पास से निकल कर लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करती हुई राजापुर ग्राम से दक्षिण यमुना नदी में अपने जल प्रवाह को अर्पित कर यमुना के जल प्रवाह की वृद्धि में अपना सहयोग देती थी किंतु आज वह विलुप्त हो चुकी है।

फैजाबाद जनपद से बहने वाली करीब आधा दर्जन नदियां समाप्त होने के कगार पर हैं। गोमती नदी तो अभी किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं किंतु उसकी अन्य सहायक नदियां तिलोदकी, तमसा, मड़हा, बिसुही और कल्याणी समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं

अयोध्या में तिलोदकी का मेला तो लगता है किंतु तिलोदकी नदी गायब हो चुकी है। सोहावल के पंडित पुर से निकली तिलोदकी नदी का उद्भव स्थल ऋषि रमणक की साधना का केंद्र रहा है। मड़हा और बिसुही नदी पूर्ण रूप से सूख चुकी हैं और अब बरसात में ही जलयुक्त दिखाई देती हैं।

वेदों में उल्लिखित पवित्र कल्याणी नदी की धारा भी सूख गई है। शासन के प्रभाव से बाराबंकी जिले में उसको पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार सहारनपुर की पांवधोई नदी उल्लेखनीय है जो पिछले 50 साल में शहर के गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी।

आज भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां समाज की जीवनदायिनी इन छोटी नदियों का अस्तित्व समाप्त प्राय न हो। इन्हीं नदियों के बल पर यमुना को विशाल जल राशि प्राप्त होती थी जो यमुना के माध्यम से गंगा को अविरल रूप से प्राप्त होती रही किंतु इन नदियों के समाप्त हो जाने से गंगा को भी अपेक्षित चल राशि की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कुंभ के दौरान भारत सहित देसी विदेशी 9 देशों (इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, साउथ कोरिया, हांगकांग, नेपाल व भारत के पचास कलाकारों ने छोटी नदियों को बचाने के लिए कलाकृतियां बनाकर लोगों को जागरूक किया।

लुप्तप्राय इन छोटी नदियों को जीवन देने के प्रयास में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ईस्टर्न यूपी रिसर्च एंड वाटर रिजर्वाटर्स मॉनिटरिंग कमेटी ने कुशीनगर की हिरण्यवती, कुकुत्था नदी समेत पूर्वांचल की 6 नदियों की सैटेलाइट मैपिंग रिपोर्ट शासन से मांगी है। एनजीटी ने यह कदम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पूर्वांचल नदी मंच के संयोजक प्रोफेसर राधे मोहन मिश्र के इन नदियों को जीवन देने के प्रयास पर उठाया है।

नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट जल संचयन योजना के अंतर्गत नदी की सफाई कराने उसके क्षेत्र को गहरा और चौड़ा कराने, किनारों पर पौधारोपण कराने और गांव के मध्य चेक डैम का निर्माण कर बारिश के पानी को रोकने का निर्देश शासन स्तर से जारी किया गया है।

भविष्य में लोगों के लिए उक्त नदियों की स्थिति मात्र कहानी किस्सों की बात बन कर रह जाएगी। इसी प्रकार ही उरई में स्थित नून नदी अपनी अंतिम अवस्था में हैं, उसका जल प्रवाह पूरी तरह से बाधित हो चुका है। जल प्रवाह के स्थान पर काले गंदे पानी से युक्त गंदा नाला प्रवहमान दर्शित होता है। तीन दशक पूर्व वह पूर्णरूपेण जल प्लावित नदी थी तथा अपने जल से जीव–जंतुओं सहित प्रकृति को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करती थी, बांध के निर्माण तथा रेत के वैध अवैध खनन के लिए सरकारी कागजों में शासन व्यवस्था उसे नदी अवश्य मानती है, लेकिन जैसे ही उसके संरक्षण संवर्धन के लिए उसके प्रदूषित होने का जिक्र कर उसे प्रदूषण मुक्त कर नव जीवन प्रदान करने की बात होती है तो उसकी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे भू माफिया तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रेत खनन के वैध अवैध व्यवसाई गण उसे बरसाती नाला बताने से नहीं चूकते। यह अलग तथ्य है कि नदी के रूप में अपने मृदुल जल से युक्त होने पर समीपवर्ती गांव के किनारे से गुजरते हुए वह उनका सहारा हुआ करती थी। वह क्षेत्र भूगर्भ जल की दृष्टि से डार्क जोन की श्रेणी में आता है। जालौन जिले के लगभग 101 गांव पूर्ण रूपेण नून नदी के जल में ही निर्भर थे, यह उनके लिए जीवनदायिनी थी किंतु उसके अस्तित्व समाप्त होने से संबंधित गांवों में पानी की विकराल समस्या मुंह बाए खड़ी है।

छोटी–छोटी नदियों को उनके अपने अस्तित्व के लिए राम भरोसे छोड़ दिया गया है ,जिससे वह स्वयं तो समाप्ति के कगार पर हैं ही साथ ही उनके द्वारा बड़ी नदियों को जल की आपूर्ति न हो पाने के कारण बड़ी नदियों के समक्ष भी समस्या मुंह बाए खड़ी है। दुर्भाग्य से भारत के नीति नियंताओं ने प्रकृति के स्रोतों का निरंतर दोहन कर उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करने का ही निरंतर प्रयास किया है, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। प्रकृति के स्रोतों को बनाए रखने के लिए छिटपुट प्रयास तो देखे जा रहे हैं किंतु शासकीय व्यापक प्रयास न किए जाने से उनका परिणाम सामने नहीं आ रहा है।

नदी के जल से आपूरित होकर भूगर्भ का जल जो कभी भूतल के समीप रहता था, अब निरंतर नीचे जा रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में शीघ्र ही भयंकर जल की समस्या उत्पन्न होगी ,जिस का निदान कर पाना बहुत आसान न होगा। उसके लिए छोटी नदियों को गति एवं जीवन प्रदान करना आवश्यक होगा, जिसे देखते हुए शासन व्यवस्था को इस दिशा में कार्य करना चाहिए किंतु ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा। जल ही जीवन है को चरितार्थ कर तथा उसके निहितार्थ को समझकर जीव–जंतुओं सहित प्रकृति को जीवन प्रदान करने वाली छोटी छोटी नदियों को सुरक्षा संवर्धन एवं प्रदूषण से संरक्षण ही उनको जीवन प्रदान कर सकता है। हिंदू धार्मिक त्योहारों गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा आदि के अवसर पर जनमानस छोटी छोटी नदियों से लेकर बड़ी–बड़ी नदियों तथा स्थानीय तालाबों जलाशयों तक को महत्व प्रदान कर, उनमें स्नान कर उनकी पूजा–अर्चना करते हैं किंतु यह भावना व्यक्तिपरक तथा मात्र एक दिन के लिए होती है, जबकि आवश्यकता है कि यह भावना व्यक्तिपरक होने के स्थान पर समाजपरक हो तथा शासन व्यवस्था बड़ी नदियों के साथ ही छोटी नदियों के संरक्षण संवर्धन एवं उनके प्रदूषण मुक्त होने को सुनिश्चित करने का दायित्व स्वयं निभाये, तभी यह नदियां बचेगी तथा धरती में जल होगा और उससे जीवन भी सुरक्षित बना रहेगा अन्यथा समाप्त होती जा रही छोटी छोटी नदियां धरती से समाप्त हो रहे जल की सूचना प्रदान कर आगे आने वाले जीवन के समक्ष उपस्थित होने वाले संकट की चेतावनी भी दे रही हैं, जिसका समय रहते निदान खोजना आवश्यक है और यह निदान किसी भी रूप में येन केन प्रकारेण छोटी छोटी नदियों को तात्कालिक लाभ की दृष्टि से बांध देने, मार देने के स्थान पर उन्हें अनवरत अपने गंतव्य पथ पर जाने हेतु प्रवाहित होने देने तथा उसकी व्यवस्था कर उसे सुनिश्चित करने से ही संभव है अन्यथा समक्ष विकराल स्थिति है, जिसका सामना कर पाना अत्यंत कठिन होगा। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

मंदी के माहौल में विकसित देशों की मदद करता भारत

कई विकसित देशों में जब मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है एवं वे देश आर्थिक समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं, ऐसे समय में भारत की एयर इंडिया कम्पनी ने अमेरिका एवं फ्रांस जैसे विकसित देशों की कम्पनियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा विमान समझौता सम्पन्न किया है। इस सौदे के बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका एवं फ्रांस के साथ ही ब्रिटेन में भी अब मंदी की आशंका कम हो सकती है क्योंकि अमेरिका एवं फ्रांस की कम्पनियां जो विमान भारत को प्रदान करेंगी उनका इंजन एवं अन्य कलपुर्जे ब्रिटेन की कम्पनियों द्वारा बनाये जाते है। अतः उक्त सौदे से ब्रिटेन को भी बहुत लाभ होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की आशंका के बीच भारत में हो रहे आर्थिक विकास के चलते अब यह कहा जाने लगा है कि भारत कई देशों में आने वाली आर्थिक मंदी को टालने में म ददगार हो सकता है। अभी तक तो भारत को एक गरीब देश की संज्ञा दी जाती रही एवं इन्हीं देशों द्वारा इसे सपेरो का देश भी बताया जाता रहा है। परंतु, भारत अब पूर्ण रूप से बदल चुका है तथा कई विकसित देशों की आर्थिक मदद करने की स्थिति में पहुंच चुका है।

एयर इंडिया कम्पनी के संचालन का दायित्व हाल ही में टाटा समूह को सौंप दिया गया था एवं टाटा समूह ने 27 जनवरी 2023 को ही एयर इंडिया के अधिग्रहण का एक साल पूरा किया है। अब टाटा समूह एयर इंडिया का कायाकल्प करते हुए विमानन के क्षेत्र में नए व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 8,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 640,000 करोड़ रुपए) मूल्य के 470 नए विमानों की खरीद कर रहा है। इसी संदर्भ में एअर इंडिया ने अमेरिका की बोइंग कम्पनी से 220 विमान एवं फ्रांस की एयरबस कम्पनी से 250 विमान खरीदने की घोषणा की है। अमेरिका की बोइंग कम्पनी एवं फ्रांस की एयरबस कम्पनी के साथ एयर इंडिया का ऐतिहासिक सौदा हालांकि 470 विमानों के लिए हुआ है परंतु इसका स्वरूप और बड़ा भी हो सकता है क्योंकि एयर इंडिया के पास अगले 10 वर्षों के दौरान अतिरिक्त 370 विमान खरीदने का विकल्प भी मौजूद है, इस प्रकार यह संख्या बढ़कर 840 विमानों तक भी जा सकती है। यह विमान सौदा विश्व के इतिहास में अभी तक किए गए सबसे बड़े विमान सौदों में से एक है। इसके पूर्व अमेरिकन एयरलाइन कम्पनी ने वर्ष 2011 में 460 विमान एक साथ खरीदे थे।

एयर इंडिया की स्थापना टाटा समूह ने वर्ष 1932 में की थी एवं वर्ष 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद से चूंकि एयर इंडिया कम्पनी की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई, अतः 7 दशकों बाद इसका अधिग्रहण पुनः टाटा समूह द्वारा कर लिया गया। टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद एयर इंडिया का विमान खरीदने सम्बंधी यह पहला सौदा है एवं पिछले 17 साल में भी यह पहला मौका है जब एयर इंडिया विमान खरीद का सौदा सम्पन्न करने जा रहा है। विमान खरीदने के साथ ही एयर इंडिया द्वारा सीएफएम इंटरनेशनल (सीएफएम), रोल्स–रॉयस और जीई एयरोस्पेस के साथ इंजनों के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए भी समझौता सम्पन्न कर लिया है। यह समझौता एयर इंडिया को विश्व स्तरीय एयरलाइन में बदलने और भारत को दुनिया के हर बड़े शहर से सीधे जोड़ने की टाटा समूह की आकांक्षा को दर्शाता है।

कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे गूगल, माइक्रसॉफ़्ट, फेसबुक, आदि कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं ऐसे समय में भारतीय कम्पनी एयर इंडिया 470 विमान एक साथ खरीद रही है। यह अपने आप में भारत की बदलती आर्थिक तस्वीर की कहानी है।

– प्रहलाद सबनानी

आज भारत में हवाई यात्रा के मामले में बहुत प्रभावशाली वृद्धि दर दर्ज हो रही है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में एक साथ विमान खरीदे जा रहे हैं। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष 2022 में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 12.32 करोड़ यात्री रही थी, जो आगे आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ने जा रही है। इसी प्रकार, एयरपोर्ट की संख्या भी वर्ष 2014 में केवल 74 थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 140 हो गई एवं वर्ष 2025 में भारत में एयरपोर्ट की संख्या 220 हो जाने की सम्भावना है। भारत में वर्ष 2014 में केवल 400 विमान थे जो वर्ष 2022 में बढ़कर 710 हो गए एवं वर्ष 2025 में विमानों की संख्या 1200 हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार एवियेशन क्षेत्र में अगले दो वर्षों में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होने जा रहे हैं।

अमेरिका के लिए उक्त समझौता आर्थिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि उक्त समझौते के सम्पन्न होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडन ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर चर्चा करते समय इस समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि एयर इंडिया एवं बोईंग के बीच सम्पन्न हुए इस ऐतिहासिक समझौते से भारत एवं अमेरिका के आपसी रिश्ते भविष्य में और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय 'व्हाइट हाउस' की एक घोषणा के अनुसार, बोइंग और एअर इंडिया एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसके तहत एअर इंडिया बोइंग से 3,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर में 220 विमान खरीदेगी। इनमें 190 बी737 मैक्स 20 बी787, और 10 बी777एक्स शामिल हैं। इस समझौते के अंतर्गत 70 और विमान खरीदने का विकल्प होगा जिससे कुल लेन–देन का मूल्य 4,590 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। उक्त समझौते से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह ऐसे समय पर होने जा रहा है जब पूरा विश्व ही एक तरह से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

अमेरिका के साथ ही एयर इंडिया ने फ्रांस के एयरबस कम्पनी से भी 250 विमान खरीदने की घोषणा की है। इनमें से 40 बड़े आकार के ए350 और 210 छोटे आकार के विमान होंगे। इन विमानों की खरीद के लिए एयर इंडिया द्वारा एयरबस कम्पनी के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री एमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे। बड़े आकार के विमान का इस्तेमाल लंबी दूरी की उड़ानों के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 16 घंटे से अधिक की उड़ानों को लंबी दूरी की उड़ान कहा जाता है। आज फ्रांस, भारत के साथ हुई उसकी स्ट्रेटेजिक सहभागिता को लेकर बहुत प्रसन्न है।

इसी प्रकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक ने भी इस समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है एवं कहा है कि उक्त सौदे का सीधा सीधा लाभ ब्रिटेन को भी मिलेगा क्योंकि इन विमानों के इंजन का निर्माण ब्रिटेन की रोलस रोयस कम्पनी करती है एवं अन्य कई पुर्ज़ों का निर्माण भी ब्रिटेन में ही किया जाता है। अतः ब्रिटेन में हजारों की संख्या में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन के साथ साथ भारत को भी उक्त सौदे से बहुत लाभ होने जा रहा है। एक तो फ्रांस ने घोषणा की है कि वह भारत में विश्व की सबसे बड़ी एयर क्राफ़्ट मेंट्नेन्स वर्क्शाप खोलने जा रहा है। इस प्रकार, भारत एवियेशन क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा मेंट्नेन्स हब बनने जा रहा है। इससे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी एवं रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होंगे। साथ ही, निकट भविष्य में भारत एवीएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। कई आकलनो के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। अभी तो केवल यह शुरुआत भर हुई है। एयरो स्पेस मैन्युफ़ैक्चरिंग के क्षेत्र में भी भारत में बहुत एवेन्यूज खुल रही हैं। दूसरे, इतने बड़े सौदे को सम्पन्न होते देखकर अब ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत की शर्तों के अनुसार शीघ्र सम्पन्न हो सकता है। तीसरे, अब रूस भी भारत के साथ अपने सुरक्षा सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। साथ ही, भारत के सम्मान की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी खबर है अतः अब अन्य देशों का भी भारत पर विश्वास और बढ़ेगा।

भारत हालांकि एक विकासशील देश है परंतु आज वह विकसित देशों की मदद करने के मामले में बहुत आगे आ रहा है। अभी हाल ही में भूकम्प के कारण संकट में आए तुर्की एवं सीरिया को भी भारत ने भरपूर मदद पहुंचाई है, बगैर यह विचार किए कि पूर्व में तुर्की एवं सीरिया दोनों ही देश भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने 150 देशों को दवाईयां, मेडिकल इक्विप्मेंट एवं वेक्सीन आदि सामान पहुंचा कर उनकी निस्वार्थ भाव से मदद की है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह गर्व का विषय हो सकता है कि भारतीय उद्योग अब इतने बड़े हो गए हैं कि वे अन्य विकसित देशों में रोजगार के अवसर निर्मित करने की क्षमता रखते हैं। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जैसे गूगल, माइक्रसॉफ़्ट, फेसबुक, आदि कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं ऐसे समय में भारतीय कम्पनी एयर इंडिया 470 विमान एक साथ खरीद रही है। यह अपने आप में भारत की बदलती आर्थिक तस्वीर की कहानी है। ❑❑

स्वावलंबन से बनेगा भारत बडी अर्थव्यवस्थाः सतीश कुमार

स्वदेशी जागरण मंच ने स्वावलंबी भारत अभियान के तहत देश में युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने का संकल्प' करने का आह्वाहन किया है। स्वदेशी जागरण मंच के सह–संगठक श्री सतीश कुमार ने कहा कि हमें देश के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए युवाओं को स्वावलंबी बनना जरुरी है।

श्री सतीश कुमार ने कहा कि इस वक्त हमारे देश में लगभग 8 प्रतिशत युवा लोग नौकरी मांगने की कतार में हैं, जो कि लगभग 4 करोड़ होते हैं। अगर ये चार करोड़ स्वावलंबी हो जाए तो देश की ग्रोथ का ईंजन बन सकते हैं।

हाल ही में सीआईआई ने कहा है कि अगर ये 8 करोड़ लोग स्वावलंबी हो जाए तो देश 40 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौकरियां तो सीमित हैं, लेकिन रोज़गार असीमित है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ऐसे में नौकरियां तो सीमित है, रोजगार की संभावनाएं अनंत है। लिहाजा स्वावलंबन के जरिए ही खुद को और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि देश में 90 हज़ार से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए हैं। इस अभियान के जरिए हम युवाओं को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित करने जा रहे है। साथ ही हम देश के सभी जिलों में रोज़गार सर्जन केंद्र खोल रहे हैं। इन रोज़गार सृजन केंद्रों में युवाओं को नौकरी खोजने, तकनीकी अपग्रेड, बिजनेस आइडियाज़, डीपीआर और लोन दिलाने तक की सेवाएं दी जाएंगी।

इस संकल्प दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. चिन्मय पांडया ने कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है। भारत के स्वाभिमान को जगाने के लिए काम हो रहा है। हमें देश में उद्यमिता को जगाने की जरुरत है। भारतीय गायत्री परिवार के सभी लोग इस उद्यमिता को लेकर काम करेंगे। जितने भी जिलों में गायत्री परिवार और उनकी शाखाएं हैं, वो मिलकर गायत्री परिवार के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जागे और लोगों को खुद के बिजनेस के लिए ट्रेंड करना चाहिए।

इस कार्यक्रम के विशिष्ठ अथिति और देश के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा कि जब मैंने खिताब जीते तो सोचा कि जब मैं खेल में इतना आगे बढ़ सकता हूं तो बाकी भी बढ़ सकते हैं। ये सोचकर मैंने 2004 में अकादमी शुरु की। हमें बस मानसिकता को ही बदलना है। चाहे वो खेल में हो या फिर इंटरप्रोन्योरमेंट के लिए हो।

स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय सह–समन्वयक डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि आज तक हम देश के 450 जिलों में रोजगार सृजन केंद्र खोल चुके हैं। बहुत ही जल्द देश के सभी जिलों में ये केंद्र खुल जाएंगे।

प्रसिद्ध मोटिवेटर स्पीकर और कार्यक्रम में विशिष्ट अथिति भूपेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि किसी बहुत बड़ी कंपनी में नौकर बनने की बजाए अपनी छोटी कंपनी होना बेहतर है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले खुद फैसला करें और फिर कौन का उद्योग अपनाना है, इस पर सोचें। जब ये हो जाए तो इस काम में जुट जाएं।

कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद देते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक प्रो. भगवती प्रकाश ने कहा कि भारत पुरातन काल से ही उद्यम प्रधान देश रहा है। भारत का हर गांव मिनी गणराज्य रहा है। लिहाजा भारत का प्रत्येक जिला अगर आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बढ़े तो भारत बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। कार्यक्रम में मंच संचालन पहले इंडिया फाउंडेशन के एक्सि क्यूटिव डायरेक्टर रवि पोखरना ने किया।

https://www.swadeshnews.in/newdelhi/india-can-become-the-worlds-largest-economy-with-self-reliance-857268

प्राचीन काल से भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाः डॉ कृष्ण गोपाल

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला रोजगार सृजन केंद्र के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ कृष्ण गोपाल ने कहा कि भारत हजारों वर्ष पूर्व से दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था था। यह हम भारत के लोग नहीं कहते, बल्कि इसको पूरे विश्व ने स्वीकारा है।

पूसा में चल रहे राष्ट्रीय युवा उद्यमिता सम्मेलन में भाग ले रहे युवाओं को संबोधित करते हुए डॉ कृष्ण गोपाल ने कहा कि पहले केवल यह माना जाता था कि भारत केवल

एक धार्मिक और कृषि प्रधान देश है मगर यह सिर्फ और सिर्फ आधा सच है। भारत लगभग हर चीज विदेशों में एक्सपोर्ट करता था जिसमें ज्वेलरी की आइटम, दवाइयां, परफ्यूम, तलवारे, मसाले, आइवरी आइटम्स आदि प्रमुख तो थे ही। साथ ही दुनिया को बड़े–बड़े पानी के जहाज भी एक्सपोर्ट करता था।

उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, दुनिया का कोई भी बड़ा अस्पताल भारत के डॉक्टरों के बिना नहीं चल सकता तथा दुनिया की बड़ी–बड़ी कंपनियां भारत के इंजीनियरों के बिना भी नहीं चल सकती। आज इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ गया है। हम गर्व से कह सकते हैं 1947 से पहले का भारत अब नहीं है। अब भारत एक मजबूत और सशक्त देश है।

राष्ट्रीय युवा उद्यमिता सम्मेलन के मुख्य अतिथि कैलाश खेर द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान पर तैयार किया गया नया गीत "हम सब को आगे बढ़ना है" का वीडियो लांच किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक सतीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तिका "स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत" का अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया गया।

कार्यशाला में जोहो कारपोरेशन के सीईओ श्रीधर वेम्बू, आईसीएआर के डीजी हिमांशु पाठक, हरियाणा से सांसद सुनीता दुग्गल, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर सुंदरम, सह संयोजक अश्वनी महाजन, प्रांत संयोजक विकास चौधरी, स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक डॉ भगवती प्रकाश, सह समन्वयक डॉ राजीव कुमार, अर्चना मीना, जीतेन्द्र गुप्त सहित विभिन्न 18 से अधिक संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं देश भर से आये लगभग 1800 से अधिक युवा मौजूद रहे।

https://panchjanya.com/2023/02/17/267348/bharat/dr-krishna-gopal-said-that-india-is-also-the-biggest-economy-of-the-world/

विश्व के कई देशों ने अपनाया भारत का यूपीआई

आज के समय में यूपीआई लोगों के लिए लेन–देन का सबसे आसान और भरोसेमंद ऑप्शन है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत करने के बारे में सोचा तो, यहां कितना कामयाब हो सकेगा इसका कोई भरोसा नहीं था। हर किसी को इस पर संदेह था।

सबसे बड़ा सवाल यह था कि कम पढ़े–लिखे लोग, कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले और पिछड़े इलाकों में इसे कैसे सफल बनाया जाएगा। यहां तक कि देश के बड़े–बड़े अधिकारियों और मंत्रियों को भी इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था।

हालांकि, इस सब चुनौतियों के बाद भी वित्त मंत्रालय के विभाग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 11 अप्रैल, 2016 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) जैसे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आज यह विश्व का सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का ऐप बन गया है, जिसे आज विश्व के कई देश अपने देश के पेमेंट ऐप के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज के समय में यूपीआई डिजिटल पेमेंट के मामले में रोज एक नया इतिहास रचने की ओर बढ़ने लगा है।

इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज देश में मोबाइल नंबर के जरिए डिजिटल लेन–देन करना इतना आसान बन चुका है, जिसको कभी एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जाता था। लेन–देन में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपीआई के उपयोग ने भुगतान की प्रक्रिया के लिए भारत को वर्तमान में सबसे टॉप देश बना दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2022 में हर सेकेंड यूपीआई के 2348 ट्रांजेक्शन हुए हैं।

देश की केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सम्मेलन के दौरान दावे के साथ कहा था कि आज के समय में विश्व के कई देश यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपने देश के पेमेंट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने बताया था कि एनपीसीआई इन दिनों यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतरीन पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अन्य देशों से जुड़कर उनकी मदद कर रहा है।

वर्तमान के डिजिटल लेन–देन के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले पांच सालों में यूपीआई का लक्ष्य प्रति दिन 1 बिलियन लेन–देन को पार करना है।

सितंबर 2021 में, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स

लिमिटेड (एनआईपीएल) ने लिक्विड ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए उत्तर और दक्षिण एशिया के 12 देशों में यूपीआई भुगतान की सुविधाजनक हो गया था। इस समझौते से यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में यूपीआई की जरूरत और मांग तेजी से बढ़ सकती है।

भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने का समझौता सबसे पहले नेपाल के साथ हुआ था। एनपीसीआई की इंटरनेशनल ब्रांच एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने नेपाल में फरवरी, 2022 से सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट्स सर्विस (जीपीएस) और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है।

सिंगापुर के बाद अब यह संख्या 10 हो गई है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूके शामिल है, जिनमें यूपीआई से पेमेंट संभव हो सकता है।

साल 2021 के डेटा के मुताबिक, इस समय देश में 940 अमेरिकी डॉलर की लेन–देन हुई थी, जो उस साल की भारत के जीडीपी का 30 प्रतिशत था। उस समय ही देखा गया था कि 80 प्रतिशत लेन–देन पीयर–टू–पीयर किया गया था, जिसमें 59 प्रतिशत लेन–देन 500 रुपये से कम मूल्य में किया गया था।

इससे साबित हो गया था कि डिजिटल पेमेंट ऐप का इस्तेमाल छोटे तबके के लोग भी करने लगे हैं। इसको भारत ने एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया।

कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) के मुताबिक, यूपीआई ने 160 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसने इसे विश्व का सबसे बेहतरी डिजिटल पेमेंट इंटरफेस बना दिया। वर्तमान में 300 से अधिक बैंक ने यूपीआई प्लेटफॉर्म से खुद को जोड़ लिया है और कहा जा सकता है कि आज यूपीआई डिजिटल पेमेंट के मामले में विश्व पर राज कर रहा है।

ऐसा इसलिए है, क्योंकि यूपीआई न केवल आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि यह दूसरे देशों के लिए भी ट्रांजेक्शन को आसान बना रहा है।

यूपीआई से लेन–देन ने लोगों को आसानी से खर्च करने में सक्षम बनाया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ है। इससे बैंकिंग प्रणाली बन गई है, जो सुरक्षित और पारदर्शी है। यूपीआई इंटरफेस के साथ लोन उद्योग में विस्तार आया है। लोन भुगतान की आसान पहुंच ने दुनिया में यूपीआई की मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया है।

यूपीआई की वृद्धि ने वित्तीय टेक्नोलॉजी (फिन–टेक) जैसे अन्य व्यावसायिक समाधानों को विस्तार दिया है। अब उच्च दर पर लोन के लिए पारंपरिक ऋण प्रदाता के पास जाने के बजाय मोबाइल ऐप के माध्यम के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

यूपीआई के माध्यम से लाया गया एक अन्य बदलाव सेविंग पैटर्न है। अब लोगों को किसी भी तरह के लेन–देन के लिए हाथ में नकदी रखने की जरूरत नहीं है। जब भी उन्हें जरूरत हो, वे बिना किसी चिंता के यूपीआई के माध्यम से आसानी से कितनी भी बड़ी रकम का लेन–देन कर सकते हैं। हालांकि, हर किसी के लिए समान पेमेंट लिमिट नहीं है। यह न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र के विकास में मदद करता है।

https://www.jagran.com/business/biz-many-countries-want-to-connect-indias-online-payment-app-upi-with-their-own-app-know-all-its-specifications-23381680.html

टेक कंपनियों ने छह माह की 5.38 लाख कार्मिकों की छंटनी

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और मंदी की आशंका के बीच पिछले छह महीने में पूरी दुनिया में 760 कंपनियों ने 5.38 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। टेक कंपनियों ने सबसे ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, जो कुल छंटनी का करीब एक तिहाई हिस्सा है। इसके अलावा, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन, वित्तीय क्षेत्र, हेल्थकेयर व ऊर्जा समेत अन्य सभी क्षेत्रों में छंटनी हुई है।

आंकड़ों के मुताबिक, कुल 5.38 लाख में से आधे की छंटनी तो केवल 24 कंपनियों ने ही की है। इसका सबसे कम असर ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों पर पड़ा है। इस क्षेत्र में छह महीने में सिर्फ 4,000 नौकरियां गई हैं।

एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विटजरलैंड का सबसे बड़ा बैंक यूबीएस भी 36,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। यह पिछले छह महीने में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी छंटनी होगी। वित्तीय क्षेत्र में हुई कुल छंटनी का यह करीब 29 फीसदी है। दरअसल, यूबीएस ने संकट में फंसे क्रेडिट सुइस का पिछले महीने अधिग्रहण किया था। इसके साथ ही यूबीएस ने कहा था कि वह 2027 तक अपनी लागत 8 अरब डॉलर तक घटाएगा। इसमें छंटनी भी शामिल होगी।

फेडेक्स ने इस दौरान कुल 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। यह लॉजिस्टिक क्षेत्र में कुल छंटनी का चार फीसदी हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 11,120 कर्मचारियों की छुट्टी की। यह टेक क्षेत्र में कुल छंटनी का पांच फीसदी है। इसके अलावा अमेजन–27101, मेटा–21000, एसेंचर–19000, अल्फाबेट–19000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है।

आइकिया ने रिटेल में कुल छंटनी का छह फीसदी यानी 10,000 लोगों को बाहर निकाला।

स्वास्थ्य क्षेत्र में फिलिप्स ने 13 फीसदी यानी 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। फीसदी के लिहाज से देखें तो यूबीएस–क्रेडिट सुइस सबसे आगे है।

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर के मोर्चे पर सख्त रुख अपनाया। इसका सीधा असर दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं और कंपनियों की कमाई पर पड़ा है। राजस्व में कमी के बीच अपनी लागत घटाने और मुनाफा स्थिर रखने के लिए कंपनियों ने छंटनी का रास्ता अपनाया हुआ है। खासकर टेक कंपनियों ने।

वैश्विक मंदी के बीच सबसे पहले इन्हीं टेक कंपनियों ने छंटनी की शुरुआत की क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने उच्च वेतन पर जरूरत से ज्यादा भर्तियां कर ली थीं।

इस साल के अनुमान पर विशेषज्ञों ने कहा कि हालात अब भी बेहतर नहीं हुए हैं। इसलिए, कंपनियां आगे और छंटनी कर सकती हैं। भारत पर भी इसका असर पड़ेगा।

https://www.amarujala.com/business/business-diary/5-38-lakh-layoffs-worldwide-in-six-months-highest-among-tech-companies-2023-04-11

40 करोड़ लोगों को मिला 23.2 लाख करोड़ का मुद्रा लोन

सूक्ष्म, लघु व मध्यम स्तर के उद्योगों (एमएसएमई) को बिना कुछ गिरवी रखे आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराने वाली मुद्रा योजना के तहत आठ वर्ष में 40 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 23.2 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। इसके लाभार्थियों में 51 आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 68 फीसदी ऋण खाते महिलाओं के नाम खुले हैं। एमएसएमई के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के मकसद से शुरू की गई इस ऋण योजना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1.12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है।

योजना के कुल लाभार्थियों में से आठ करोड़ (21 फीसदी) पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। ये वे लोग हैं, जिनकी कारोबारी या व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। इस योजना में शिशु ऋणों के त्वरित पुनर्भुगतान पर ब्याज में दो फीसदी

की छूट भी मिलती है।

योजना के तहत व्यवसाय की परिपक्वता स्थिति के आधार पर शिशु, किशोर व तरुण श्रेणियों में ऋण दिया जाता है। शिशु श्रेणी में 50,000 रुपये, किशोर श्रेणी में 5 लाख रुपये तक और तरुण श्रेणी में 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं।

कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे– पोल्ट्री, डेयरी, मधुमक्खी पालन। इसके अलावा विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों की गतिविधियों के लिए इस योजना के तहत ऋण दिया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को योजना को भारतीयों के लिए अपना उद्यमिता कौशल दिखाने का जरिया बाताते हुए कहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अनफंडेड की फंडिंग कर अनगिनत भारतीयों के लिए सम्मान के साथ–साथ समृद्धि का जीवन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। आज, मुद्रा योजना के आठ वर्ष पूरे होने पर उन सभी लोगों की उद्यमशीलता और उत्साह को सलाम है, जो इससे लाभान्वित हुए और धन सृजक बने।

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना से एमएसएमई के विकास ने मेक इन इंडिया में व्यापक योगदान दिया है, क्योंकि मजबूत घरेलू एमएसएमई की बदौलत घरेलू बाजारों के साथ–साथ निर्यात भी काफी अधिक बढ़ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिहाज से यह गेम चेंजर साबित हुई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक योजना का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा, पीएमएमवाई का उद्देश्य एमएसएमई को औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना और छोटे कारोबारियों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालना है। उन्होंने बताया कि योजना के तीन प्रमुख आधार हैं। पहला, बैंकिंग सेवाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। दूसरा, असुरक्षित को सुरक्षित करना और तीसरा वित्त से वंचितों का वित्त पोषण करना। ❑❑

https://www.amarujala.com/business/business-diary/government-distributed-more-than-23-lakh-crore-mudra-loan-in-eight-years-2023-04-09

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

युवा संकल्प दिवस

23 मार्च 2023

सचित्र झलक

भोपाल, म.प्र.

चम्पावत, उत्तराखंड

हरदोई, उ.प्र.

हिसार, हरियाणा

उत्तरकाशी, उत्तराखंड

शाहदरा, दिल्ली

वसंत जिला, दिल्ली

नर्मदापुरम्, म.प्र.

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अप्रैल 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

युवा संकल्प दिवस

23 मार्च 2023

सचित्र झलक

केंद्रीय कार्यालय, दिल्ली

उड़ीसा

आगरा, उ.प्र.

बैतूल, म.प्र.

बाड़मेर, राजस्थान

बाराबंकी, उ.प्र.

डार्जिलिंग, प. बंगाल

सरायकेला, झारखंड

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती